page 1 and 8 July 18_page 1 Mar 25 final ds.qxd 7/18/2026 1:38 AM Page 1

epaper.dehatsandesh.com

3 डीसी उधमपुर ने मनसर में जन शिकायत निवारण शिविर लगाया

5 पीवी सिंधु जापान ओपन सेमीफाइनल में

8 स्वतंत्रता दिवस 2026 समारोह की तैयारियों की डीसी सांबा ने समीक्षा

मौसम जम्मू — न्यूनतम 25 — अधिकतम 36

E-mail: dehatsandesh@gmail.com

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

देहात संदेश

वर्ष-23, जम्मू तवी, अंक-179 | जम्मू तवी, शनिवार 18 जुलाई, 2026 | मूल्य-3 रूपये- (लेह) 4 रूपये | पृष्ठ -8

हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन 'मेक इन इंडिया' अभियान का एक सफल उदाहरण है: मोदी

जींद (हरियाणा) , 17 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम एशिया से तेल की आपूर्ति को प्रभावित करने वाला आज जैसा संकट 2014 से पहले आया होता तो देश में रेलवे का काम ठप पड़ गया होता। उन्होंने कहा कि उस समय देश का बड़ा हिस्सा ऐसा था जहां ट्रेने सिर्फ और सिर्फ डीजल से चलती थी लेकिन उनकी सरकार के प्रयास से आज 99 प्रतिशत रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है। प्रधानमंत्री यहां विकास की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने जींद से सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली यात्री ट्रेन को भी हरीझंडी दिखा कर रवाना किया। श्री मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेल में जो ये बड़े बदलाव हुए, इससे भारत को एक और फायदा हुआ है।

प्रधानमंत्री ने कहा, आप देख रहे हैं, कि पिछले कई महीनों से पश्चिमी एशिया में, होर्मुज के पूरे क्षेत्र में, ईरान और खाड़ी क्षेत्र में युद्ध चल रहा है, और जिस समुद्री रास्ते- होर्मुज से भारत,

बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल-डीज़ल-एलपीजी गैस तथा हमारे किसानों के लिए खाद आता है... पिछले 3-4 महीनों से यह रास्ता, निरंतर युद्ध का मैदान बन चुका है, संकटों से घिरा हुआ है।

उन्होंने कहा, अगर 2014 से पहले अगर ये स्थिति आती, तो आज हिन्दुस्तान का रेलवे का काम पूरा का पूरा ठप पड़ा गया होता। क्योंकि उस समय देश का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था, जहां हमारी ट्रेनें सिर्फ और सिर्फ डीजल से चलती थीं। अब आप सोचिए, अगर डीजल आना बंद हो गया होता, आज डीजल से चलने वाली ट्रेनें कैसे चलती? देश कितने बड़े संकट में आ जाता?

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 2014 की स्थिति नहीं है क्यों कि वह बहुत आगे की सोच कर समस्याओं के समाधान के रास्ते जमीन पर उतारते हैं। उन्होंने कहा कि लोग यह सुनकर हैरान होंगे कि विद्युतीकरण की शुरूआत 1925 में हो गयी थी पर उस समय से लेकर 2014 तक, यानी करीब 90 साल में पूरे देश के रेल नेटवर्क का सिर्फ 30 प्रतिशत या एक तिहाई से भी कम का ही विद्युतीकरण हो पाया था तथा 70 प्रतिशत नेटवर्क पर ट्रेने डीजल से चलती थीं। उन्होंने कहा कि अगर उसी गति से काम किया जाता तो पूरे नेटकर्व के विद्युतीकरण में

प्रधानमंत्री ने जींद से सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली यात्री ट्रेन को भी हरीझंडी दिखा कर रवाना किया

200 साल और लग जाते। लेकिन बीते 12 वर्षों में करीब 99 प्रतिशत रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में लड़ाई होने के कारण तेल का संकट पैदा होने के बावजूद भारत की रेल रुकी नहीं है। भारत की विकास की गाड़ी अटकी नहीं है, ट्रेनें निरंतर चलती रही हैं।

प्रधानमंत्री ने बताया कि जींद से सोनीपत के बीच चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे लम्बी हाइड्रोजन ट्रेन है। यह तीन हजार दो सौ हॉर्स पावर की है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही हैं, वो तीन या चार कोच वाली हैं और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर, दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है।

अमरनाथ यात्रा के पहले 15 दिनों में 3.5 लाख तीर्थयात्रियों ने की यात्रा पूरी : उपराज्यपाल

उपराज्यपाल ने पहलगाम में नुनवान बेस कैंप का दौरा किया जहां उन्होंने तीर्थयात्रियों को दी जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया

पहलगाम, 17 जुलाई । उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले 15 दिनों में 3.50 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन किए हैं। उन्होंने यात्रा के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन का श्रेय भगवान शिव के आशीर्वाद और सभी संबंधित पक्षों के समन्वित प्रयासों को दिया। उपराज्यपाल ने पहलगाम में नुनवान बेस कैंप का दौरा किया जहां उन्होंने तीर्थयात्रियों को दी जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया और चल रही यात्रा की व्यवस्थाओं का आकलन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की पत्रकारों से बात करते हुए सिन्हा ने कहा कि देश भर से आ रहे भक्तों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ यात्रा सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आज यात्रा शुरू हुए 15 दिन हो गए हैं और 3.50 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए हैं। बाबा अमरनाथ की कृपा से यात्रा शांतिपूर्ण और सुचारू रू द्धप से चल रही है। उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन, जेएंडके पुलिस, सेना, सीएपीएफ और यात्रा के प्रबंधन में शामिल अन्य सभी एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भक्तों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए इस साल की गई व्यवस्थाओं को काफी मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि वार्षिक यात्रा से स्थानीय व्यवसायों, परिवहन संचालकों, होटल मालिकों, टट्टू मालिकों, मजदूरों और अन्य सेवा प्रदाताओं को लाभ होगा जिससे जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीर्थयात्रियों से स्थानीय रूप से बने उत्पादों को खरीदने की अपील का जिक्र करते हुए सिन्हा ने कहा कि इस पहल से स्थानीय कारीगरों, व्यापारियों और उद्यमियों की आजीविका और मजबूत होगी ।बाद में, एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि उन्होंने नुनवान बेस कैंप में सुविधाओं का निरीक्षण किया और यात्रा के सुचारू संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक में पीने के पानी, बिजली, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, रहने और खाने-पीने की सुविधाओं जैसी ज़रूरी सेवाओं पर ध्यान दिया गया। साथ ही सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे तीर्थयात्रियों की भलाई और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड में काम करें।

खबर संक्षेप

जम्मू-कश्मीर के लिए अचानक बाढ़ की चेतावनी

जम्मू, 17 जुलाई । 20 से 25 जुलाई के बीच जम्मू-कश्मीर में मॉनसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आपस में मिलने से मौसम पर असर पड़ने की काफी संभावना है। सबसे ज्यादा बारिश 20 से 23 जुलाई के दौरान होने की उम्मीद है।

मौसम विभाग कश्मीर के अनुसार मौसम के अनुमान की सटीकता धीरे-धीरे बेहतर हो रही है और यह इस मौसम का पहला बड़ा और व्यापक बारिश का दौर हो सकता है जो कई ज़िलों को प्रभावित करेगा। जम्मू में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश हो सकती है और कश्मीर में भी भारी से बहुत ज्यादा बारिश की उम्मीद है जिसमें दक्षिण कश्मीर में बारिश की गतिविधि ज्यादा हो सकती है। दोनों क्षेत्रों के निचले इलाकों में अचानक बाढ़ भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएँ भी हो सकती है ।20-25 जुलाई के दौरान सतर्क रहें क्योंकि भारी बारिश से अचानक बाढ़ और भूस्खलन हो सकता है

गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत, एसओजी के तीन जवान घायल

भद्रवाह, 17 जुलाई। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) के तीन जवान घायल हो गए। यह घटना तब हुई जब उस व्यक्ति ने कथित तौर पर एक सर्विस राइफल छीनने की कोशिश की।

पुलिस अधिकारियों ने शुकवार को बताया कि गुरुवार देररात हुई इस घटना के सिलसिले में एक धार्मिक उपदेशक को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति का इस घटना से क्या संबंध है यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऊंचाई वाले इलाके में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद, एसओजी की एक टीम ने गुरुवार को भद्रवाह शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर जाई-गांडोह रोड पर घात लगाकर कार्रवाई की।

उन्होंने बताया कि गुरुवार - शुक्रवार की देर रात एसओजी की टीम ने एक युवक को रोका जिसने कथित तौर पर जवानों पर हमला किया और सर्विस राइफल छीनने की कोशिश की। अधिकारी ने कहा कि हाथापाई के दौरान एक एसओजी जवान ने गोली चला दी। युवक को गोली लगी जबकि घटना में तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। चारों को भद्रवाह के सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ से उन्हें बेहतर इलाज के लिए डोडा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि चीका गांव के रहने वाले युवक आरिफ हुसैन (30) की चोटों के कारण मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि एक धार्मिक उपदेशक को हिरासत में लिया गया है। एहतियात के तौर पर भद्रवाह शहर में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है। अधिकारियों ने बताया कि सेना ने जाई इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया है।

मुख्य सचिव ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) नीति के प्रारंभिक मसौदे की समीक्षा की

जम्मू-कश्मीर में निवेश आकर्षित करने के लिए मजबूत ढांचा तैयार करने पर दिया जोर

श्रीनगर, 17 जुलाई। मुख्य सचिव अतल डुल्लू ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) नीति के प्रारंभिक मसौदे पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। यह नीति योजना, विकास एवं निगरानी विभाग द्वारा सेंटर फॉर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस (सीआईटीएजी) के माध्यम से तैयार की जा रही है। इसका उद्देश्य निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना तथा जम्मू-कश्मीर में आधारभूत ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं के विकास में तेजी लाना है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि उत्पादन विभाग), अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोक निर्माण विभाग), आईआईएम जम्मू के निदेशक, आयुक्त सचिव (योजना, विकास एवं निगरानी), आयुक्त सचिव (आवास एवं शहरी विकास विभाग), आयुक्त सचिव (उद्योग), सचिव परिवहन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीआईटीएजी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने प्रस्तावित नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संस्थागत क्षमता विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों का व्यवस्थित प्रशिक्षण किया जाना चाहिए ताकि वे नीति को प्रभावी और समयबद्ध तरीके से लागू करने में सक्षम हो सकें। जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए अतल डुल्लू ने कहा कि सरकार को इस नीति के क्रियान्वयन में स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे निवेशकों और आम जनता का विश्वास मजबूत हो। उन्होंने उद्योग विभाग को निर्देश दिए कि बैठक में प्राप्त सुझावों को शामिल करते हुए नीति के मसौदे को और परिष्कृत किया जाए तथा अगले एक महीने के भीतर एक व्यापक और सुव्यवस्थित नीति दस्तावेज तैयार किया जाए।वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का उल्लेख करते हुए मुख्य सचिव ने विश्व बैंक के स्टेप मॉडल का हवाला दिया और इसे एक गतिशील तथा निरंतर विकसित होने वाला ढांचा बताया, जो न्यूनतम प्रक्रियात्मक बाधाओं के साथ परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक है।

डॉ. फारूक अब्दुल्ला पर कथित हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

जम्मू, 17 जुलाई। जम्मू के प्रधान सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला पर कथित हत्या के प्रयास के बहुचर्चित मामले में आरोपी कमल सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरोपों की गंभीरता, सार्वजनिक व्यवस्था पर संभावित प्रभाव तथा आरोपी द्वारा अपराध दोहराने की आशंका को देखते हुए उसे जमानत देना उचित नहीं होगा।

प्रधान सत्र न्यायाधीश आर. एन. वाटल ने 17 जुलाई 2026 को यह आदेश पारित करते हुए थाना गंग्याल, जम्मू में दर्ज एफआईआर संख्या 29/2026 से संबंधित जमानत याचिका को खारिज कर दिया। यह मामला भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 109 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 बाद में धारा 30 का उल्लेख के तहत दर्ज किया गया है।

आरोपी कमल सिंह की ओर से अधिवक्ता प्रिंस खन्ना ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि उनका मुवक्किल निर्दोष है, वृद्ध है तथा तंत्रिका और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से पीड़ित है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी का डॉ. फारूक अब्दुल्ला को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था और वह केवल एक विवाह समारोह के दौरान उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए उनके पास जाने की कोशिश कर रहा था। यह भी कहा गया कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है, इसलिए उसकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए जमानत दी जानी चाहिए।

मानसून सत्र

एनडीए मंत्रियों की बैठक में सरकार की प्राथमिकताओं पर मंथन, अहम विधेयकों को पारित कराने की रणनीति पर चर्चा

नई दिल्ली, 17 जुलाई। संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले शुक्रवार को कर्तव्य भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए के सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए।

सूत्रों के अनुसार बैठक में आगामी 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के लिए सरकार की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें जनता दल (यूनाइटेड) के ललन सिंह, राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी और तेलुगु देशम पार्टी के किंजारापु राम मोहन नायडू भी उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जबकि महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी इसमें शामिल हुईं। सूत्रों ने बताया कि बैठक में मानसून सत्र के दौरान सरकार के विधायी एजेंडे पर विचार किया गया। सरकार की प्राथमिकता दो अध्यादेशों को संसद से पारित कर कानून का रूप देने की है। सरकार आगामी मानसून सत्र में आयकर (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करने की तैयारी कर रही है, जो हाल ही में जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा। इस अध्यादेश के तहत विदेशी निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में निवेश से प्राप्त ब्याज और पूंजीगत लाभ पर आयकर से छूट दी गई है। यह अध्यादेश पिछले महीने पश्चिम एशिया संकट के कारण रुपये पर पड़े दबाव को कम करने तथा विदेशी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से जारी किया गया था।

एनडीपीएस अधिनियम के तहत 3.34 करोड़ रुपये की चार संपत्तियां कुर्क

श्रीनगर, 17 जुलाई। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम एनडीपीएस, 1985 की धारा 68एफ के तहत 3 करोड़ 34 लाख 51 हजार 957 रुपये मूल्य की चार अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई नशा मुक्त भारत अभियान - 100 दिवसीय अभियान के तहत की गई। सफाकदल थाना पुलिस ने एनडीपीएस मामलों की जांच के दौरान इन संपत्तियों को अवैध नशा कारोबार से अर्जित धन से खरीदी गई संपत्ति के रूप में चिन्हित किया।

जम्मू-कश्मीर का दर्जा बहाल करने के कांग्रेस के अभियान में एनसी होगी शामिल, जेपीएससी अध्यक्ष ने किया स्वागत

जम्मू, 17 जुलाई । जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेपीएससी) के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्य का दर्जा बहाल करने के अभियान में शामिल होने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन कांग्रेस ने लगभग दो साल पहले शुरू किया था और इसका मकसद हमेशा जम्मू-कश्मीर के सभी 1.4 करोड़ लोगों की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करना रहा है ।जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कर्रा ने कहा कि कांग्रेस ने शुरू से ही यह बात कही है कि ‘हमारी रियासत, हमारा हक’ अभियान किसी एक पार्टी

का आंदोलन नहीं है बल्कि यह जम्मू-कश्मीर के हर नागरिक का है चाहे उनका धर्म, राजनीतिक जुड़ाव या क्षेत्र कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सभी राजनीतिक दलों और समाज के सभी वर्गों को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों को इसका नेतृत्व करने का प्रस्ताव भी दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की भागीदारी का स्वागत करते हुए कर्रा ने कहा कि अगर पार्टी पहले शामिल हो जाती, तो बेहतर होता, लेकिन कांग्रेस उनके देर से शामिल होने के कारणों पर सवाल नहीं उठाएगी। उन्होंने कहा कि हम इस कदम का स्वागत करते हैं क्योंकि राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा जम्मू-कश्मीर के हर निवासी से जुड़ा है। जेकेपीसीसी प्रमुख ने कहा कि कांग्रेस ने इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की और लगातार इसका समर्थन किया है और जब तक राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वह अपना अभियान जारी रखेगी। कर्रा ने यह भी घोषणा की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा 20 जुलाई को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की घोषणा के बाद कांग्रेस ने अपने तय कार्यक्रम को 20 जुलाई से बदलकर 19 जुलाई कर दिया है।

सतीश शर्मा ने छंब में 10 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया

जम्मू, 17 जुलाई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, सूचना प्रौद्योगिकी, युवा सेवा एवं खेल तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सतीश शर्मा ने आज छंब विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत की अनेक महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इन विकास परियोजनाओं के माध्यम से जम्मू-कश्मीर सरकार ने आधारभूत ढांचे के विकास में तेजी लाने, जनसेवा वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने तथा ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। कार्यक्रम के दौरान सड़कों, पुलों, प्रशासनिक भवनों, खेल सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं तथा पशु चिकित्सा अवसंरचना से संबंधित 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था बेहतर होगी, आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान बनेगी, ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के नए अवसर सृजित होंगे। मंत्री ने ठंडी छोई-सैंथ सड़क का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण 1.50 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। उन्होंने कहा कि सड़क संपर्क आर्थिक विकास की रीढ़ है और बेहतर सड़कें न केवल यात्रा समय कम करती हैं, बल्कि व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच तथा क्षेत्रीय विकास को भी गति देती हैं।

एनसी आर्टिकल 370 और 35ए को खत्म करने की कोशिश कर रही है : सज्जाद लोन

श्रीनगर, 17 जुलाई। पीपल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक संघर्ष का फोकस सिर्फ़ राज्य का दर्जा बहाल करने पर नहीं बल्कि 5 अगस्त 2019 से पहले की संवैधानिक स्थिति को बहाल करने पर होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) अपने अभियान को सिर्फ़ राज्य का दर्जा बहाल करने तक सीमित रखकर आर्टिकल 370 और 35ए को खत्म करने की कोशिश कर रही है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लोन ने कहा कि आर्टिकल 370, आर्टिकल 35ए और राज्य का दर्जा मिलकर वह संवैधानिक ढांचा बनाते थे जो 5 अगस्त 2019 से पहले मौजूद था और इनमें आर्टिकल 370 सबसे महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि हम जम्मू-कश्मीर के लिए 2019 से पहले की स्थिति की बहाली चाहते हैं न कि सिर्फ़ राज्य का दर्जा। मुद्दा राजनीतिक सशक्तिकरण का है न कि सिर्फ़ राज्य का दर्जा बहाल करने का। एनसी द्वारा जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए लोन ने आरोप लगाया कि पार्टी राजनीतिक नैरेटिव को आर्टिकल 370 और 35ए से दूर ले जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनसी ने जिन मुद्दों पर वोट मांगे थे वे आर्टिकल 370 और 35ए की बहाली थे। आज सिर्फ़ राज्य का दर्जा बहाल करने की बात की जा रही है। मेरा मानना ??है कि यह उन मांगों को खत्म करने की कोशिश है। लोन ने कहा कि अगर सरकार राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर गंभीर है तो उसे इस मुद्दे को सड़कों पर ले जाने से पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, प्रस्ताव पारित करना चाहिए और प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और विपक्ष के नेता से मिलने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा अभी भी लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। सबसे पहले संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लोन ने प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन के समय पर भी सवाल उठाए और कहा कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि अगर उन बैठकों में राज्य का दर्जा बहाल करने का कोई आश्वासन नहीं मिला तो लोगों को बताया जाना चाहिए कि क्या जवाब मिला। अपनी पार्टी का रुख़ दोहराते हुए लोन ने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस राज्य का दर्जा बहाल करने का समर्थन करती है लेकिन यह समर्थन तभी होगा जब जम्मू-कश्मीर की 2019 से पहले वाली संवैधानिक स्थिति जिसमें अनुच्छेद 370 और 35 शामिल हैं को भी बहाल किया जाए।

साभार : अशोक कुमार मुनड़ेतिया

शॉपिंग के दौरान बचाने हैं पैसे तो फॉलो करें ये आसान टिप्स

शॉपिंग के दौरान अक्सर लोग अपने तय बजट से ज्यादा खर्च कर देते हैं, जो उनके बजट पर बुरा असर डालता है। इस स्थिति में उनके लिए महीने को मैनेज करना बड़ा टास्क बन जाता है। आपके साथ ऐसा न हो इसके लिए हम लाए हैं कुछ बेहद काम के टिप्स।

बनाएं लिस्ट

सबसे पहले तो इसकी लिस्ट बनाएं कि आपको क्या लेना है। लिस्ट का तरीका सिर्फ किराना लाने के लिए बल्कि कपड़ों आदि की शॉपिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस आपको अपने कपड़ों को एक बार अच्छे से देखना है और यह लिखना है कि आपके पास क्या नहीं है या किस तरह के कपड़ों की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। यह फिल्टर उन चीजों पर बिना मतलब के खर्चे से बचने में मदद करेगा।

कैरी करें सिर्फ कैश

लोग डिजिटल पैमेंट की ओर जा रहे हैं और हम कैश कैरी करें जी हां, अगर आपको अपने बजट में रहते हुए शॉपिंग करना है तो इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता। जब खर्च करने के लिए एक्सट्रा पैसे ही नहीं होंगे तो भला आप दूसरी चीजों पर खर्च ही कैसे कर सकेंगे और यही चीज आपको फालतू के खर्चों से बचा लेगी।

एक जगह न अटकें

चाहे कपड़े लेने हों या फिर किराना, किसी एक जगह न अटकें और दूसरी जगहों पर भी इन चीजों को देखे। उदाहरण के लिए कपड़ों पर एक जगह जो जींस आपको 4000 की मिल रही है, वैसी ही जींस दूसरी जगह डिस्काउंट के साथ मिल सकती है या फिर दूसरे ब्रैंड में कम कीमत पर खरीदी जा सकती है। इसी तरह मान लीजिए अगर एक ब्रैंड का लोशन 340 रुपये का मिल रहा है तो हो सकता है दूसरे ब्रैंड के लोशन पर इसी कीमत में एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। इसलिए जितना हो सके पहले एक्सप्लोर जरूर करें।

बोरियत में कुछ भी करें लेकिन शॉपिंग नहीं

बोरियत होने पर गेम्स खेलें, मूवी देखें, कुकिंग करें.कुछ भी करें लेकिन शॉपिंग नहीं। सबसे खतरनाक होती है इमोशनल शॉपिंग जो सबसे ज्यादा बिना मतलब का खर्चा करवाती है। इस तरह की शॉपिंग का एक और नुकसान यह भी होता है कि इस दौरान ली गईं ज्यादातर चीजें ऐसी होती है जिनका आप कभी यूज भी नहीं करेंगे।

ऑनलाइन देखें ऑप्शन्स

आजकल ज्यादातर ब्रैंड्स की वेबसाइट्स भी होती हैं जहां से कपड़ों को ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है। इन वेबसाइट्स पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी उपलब्ध होता है। ऐसे में आप चाहे तो स्टोर में कपड़ों को ट्राई कर सकती हैं और सही साइज मिल जाने पर उसे ऑनलाइन सर्च करें। अगर वहां ये सस्ते में मिल रहे हैं तो फिर वेबसाइट से ही इसे ऑर्डर करें।

शॉपिंग पार्टनर भी है अहम

हमें यकीन है आप में से कई लोगों ने कभी इस बात को सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आपकी फिजूलखर्ची के लिए आपके साथ शॉपिंग पर गया शख्स भी जिम्मेदार हो सकता है। अगर वह आपको बार-बार नई चीज दिखाए और कहे कि आप इसे ले लें क्योंकि यह अच्छा लगेगा, या फिर डिस्काउंट के चक्कर में ज्यादा चीजें लेने की सलाह दे तो बेहतर है कि अगली बार आप उसके साथ न जाएं। शॉपिंग पर ऐसे शख्स के साथ जाएं जो आपको फिजूलखर्ची से रोके और आपको जो लेना है उसकी ओर ध्यान केंद्रित करवाए।

जा रहे हैं सब्जी लेने तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान

सब्जी खरीदने की बात आती है तो ज्यादातर लोग बस दाम पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन सिर्फ प्राइस कम हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि यह फायदे का सौदा है। बल्कि आपको इन्हें खरीदने के दौरान ऐसी कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो सब्जी की मौजूदा क्वॉलिटी और वह कितनी जल्दी खराब हो जाएगी यह तय करते हैं।

सब्जी न हो कहीं से डैमेज

सब्जी जब लें तो उसे चारों ओर से पलटकर ध्यान से जरूर देखें। अगर उसमें जरा सा भी छेद या कट दिखाई देता है तो उसे न लें। ऐसी सब्जियों में कीड़े होने के चांस ज्यादा रहते हैं। वहीं अगर जो सब्जियां किसी हिस्से से दबी हुई हों खासतौर से टमाटर जैसी चीज तो इनके जल्दी खराब होने का डर रहता है।

हल्का सा दबाकर देखें

टमाटर हो, प्याज हो, आलू हो, गाजर हो या कोई अन्य सब्जी, उसे दबाकर जरूर देखें। हल्के से दबाव से ही पता चल जाता है कि कहीं वह सब्जी अंदर से खराब तो नहीं है। हालांकि, पत्तेदार सब्जियों पर यह तरीका काम नहीं करता है।

जब बात आए पत्तेदार सब्जियों की

पत्तेदार सब्जियों में इतने वैरायटी होती है कि सभी पर एक तरीका काम नहीं करता है। हालांकि, कुछ कॉमन बातें हैं जिनका इन्हें लेने के दौरान ध्यान रखना जरूरी है। ध्यान में रखें कि ऐसी पत्तेदार सब्जी न लें जो पानी में बहुत ज्यादा भीगी हो, इनके जल्दी खराब होने के डर रहता है। पालक, लाल भाजी जैसी सब्जियों को लेते वक्त एक-एक पत्ते को ध्यान से देख लें क्योंकि इनके बीच में कीड़े हो सकते हैं। पत्ते पीले या बड़े हों तो उन्हें न लें क्योंकि उनमें स्वाद कम होता है।

सूंघकर देखें

मार्केट में पैक्ड मशरूम, कॉर्न्स, स्प्राउट्स जैसी चीजें मिलती हैं। इन्हें जब लें तो पैकेट को नाक से थोड़ी दूर पर रखते हुए उन्हें सूंघें। अगर वे पुराने होंगे तो उनकी स्मेल बदल चुकी होगी। ऐसे पैकेट्स को न लें, नहीं तो बीमार हो सकते हैं।

उतना ही लें जितना इस्तेमाल हो जाए

कई ऐसी सब्जियां होती हैं जिन्हें सिर्फ उतना ही लेना चाहिए जितना आप इस्तेमाल कर पाएं। फ्रिज में भी ये सब्जियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाती हैं। उदाहरण के लिए धनिया और टमाटर। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप ज्यादा ले तो लें लेकिन अगर ये सिर्फ फ्रिज में ही रखी हैं तो तीन-चार दिन में ही ये खराब होना शुरू कर देंगीं।

बेड के लिए परफेक्ट चादर खरीदने में काम आएंगी ये टिप्स

क्या आप मार्केट में नई बेडशीट लेने जाने के बारे में सोच रहे हैं अगर हां तो बेहतर होगा कि आप पहले नीचे दी गई जानकारी पढ़ें लें, ऐसा करने पर शायद आप ज्यादा बेहतर चादर का सिलेक्शन कर सकेंगे।

लोग आमतौर पर बेड के गद्दों को लेने से पहले पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन जब बात आती है चादर की तो वे इस मामले को हल्के में ले लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अच्छी नींद के लिए जितना जरूरी अच्छा गद्दा है उतनी ही जरूरी चादर भी है। आप अपने बेड के लिए कैसे सही चादर चुन सकते हैं इसमें नीचे दिए टिप्स आपके काफी काम आ सकते हैं।

फैब्रिक का रखें ध्यान

सबसे बड़ी और पहली बात होती है फैब्रिक का सही सिलेक्शन करना। यह इसलिए जरूरी होता है कि क्योंकि बेडशीट का कपड़ा आपके शरीर के संपर्क में आएगा इसलिए चादर का सिर्फ सुंदर होना नहीं बल्कि कंफर्टेबल होना भी जरूरी है। इस लिहाज से कॉटन की चादर बेस्ट फिट कही जा सकती है। कॉटन न सिर्फ स्किन के अगेंस्ट कंफर्टेबल रहता है बल्कि यह ब्रिदेबल फैब्रिक भी माना जाता है, जो नमी इकट्ठा नहीं करता।

साइज

बस यूं ही चादर लेने न निकल पड़ें। आपका बेड कितने साइज का है और आपको साइड में कितनी चादर छोड़नी है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बेडशीट सिलेक्ट करें। आमतौर पर अगर आप मार्केट से चादर लेते हैं तो पैकेट पर ही साइज लिखा होता है, जो आपके काम को आसान कर सकता है। हालांकि, अगर आप बिना पैकेट वाली चादर लेते हैं तो नाप का ध्यान जरूर रखें।

वाइट- कलरफुल चादर

वाइट कलर की खासियत होती है कि यह शांत करने में मदद करता है। यही इफेक्ट सफेद चादर भी क्रिएट करती है। यह ज्यादा रिलैक्सिंग फीलिंग के साथ ही मूड को शांत करने में मदद करती है। वहीं कलरफुल चादर रूम में चियरफुल फील क्रिएट करती है। बात करें स्ट्राइप चादर की तो यह रूम को व्यवस्थित दिखाने में मदद करती है।

रिटर्न पॉलिसी

जी हां, इस बात को भूलकर भी इग्नोर न करें। कई बार होता है कि चादर लेने के बाद एक ही वॉश में सारे कलर उड़ जाते हैं। अच्छी कंपनीज अपने ग्राहकों को ऐसी स्थिति में चादर रिटर्न करने का भी ऑप्शन देती है क्योंकि यह क्वॉलिटी में खरे न उतरने वाली बात है। ऐसे में अगर आप ऐसी कंपनी की चादर ले लें जिसमें ऐसी रिटर्न पॉलिसी न हो तब तो आपकी चादर बस एक ही बार बिछाई जा सकेगी।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक - नीलम सिंह गिल द्वारा देहात संदेश, गुरूद्वारा सुंदर सिंह रोड, जम्मू से प्रकाशित एवं नार्थलाईनस पबलिशर्स, 18-B, Phase- II, Industrial Estate, Gangyal, Jammu से मुद्रित। संपादक- नीलम सिंह गिल। फोन नंबर:- (95)191- 2574109 2548103 RNI Regd. No.: JKBIL/2004/13144 *Email: dehatsandesh@gmail.com, dehatsandesh@yahoo.com, dehatsandesh@rediffmail.com*

डीसी उधमपुर ने मनसर में जन शिकायत निवारण शिविर लगाया, लोगों की समस्याएं सुनीं

उधमपुर, 17 जुलाई। उपायुक्त उधमपुर मिंगा शेरपा ने आज मजालता ब्लॉक के दौरे के दौरान मनसर में जन शिकायत निवारण शिविर आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

शिविर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री माता वैष्णो देवी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एसएमडीए) विवेक पुरी, परियोजना अधिकारी पोषण सुभाष डोगरा, सहायक आयुक्त पंचायत डॉ. अश्विनी हंसा तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

जन संपर्क कार्यक्रम में पूर्व पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा आसपास की पंचायतों के बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और अपनी विभिन्न समस्याएं एवं मांगें उपायुक्त के समक्ष रखीं। इनमें पेयजल आपूर्ति बढ़ाने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन तथा अल्ट्रासाउंड मशीन की स्थापना, प्राथमिक विद्यालय बट्टल और उच्च माध्यमिक विद्यालय मनसर में चारदीवारी निर्माण, उच्च माध्यमिक विद्यालय मनसर में पुस्तकालय, स्मार्ट कक्षाएं, सभागार और परीक्षा भवन का निर्माण, बिजली कटौती की समस्या का समाधान, पैदल मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था, महिलाओं के लिए शौचालय, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना, आंगनवाड़ी केंद्रों का युक्तिकरण, मनसर में नए पार्क और स्टेडियम का विकास, नौकाओं की संख्या बढ़ाने तथा शिकारा सेवा शुरू करने जैसी मांगें शामिल थीं।

उपायुक्त ने सभी शिकायतों और मांगों को गंभीरता से सुना तथा संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सभी शिकायतों का स्वयं स्थल पर जाकर आकलन करें और वास्तविक समस्याओं का निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करें। जन-केंद्रित और जवाबदेह प्रशासन पर बल देते हुए मिंगा शेरपा ने अधिकारियों से पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान करने को कहा।

जन्म जयंती पर गिर्धारी लाल डोगरा को भावभीनी श्रद्धांजलि, सुभाष गुप्ता बोले-जनसेवा के प्रतीक थे

कठुआ, 17 जुलाई (हि.स.)। पूर्व एमएलसी सुभाष गुप्ता ने हीरानगर मोड़ स्थित गिर्धारी लाल डोगरा चैक पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व वित्त मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गिर्धारी लाल डोगरा की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए।

इस मौके पर सुभाष गुप्ता ने डोगरा को दूरदर्शी, ईमानदार और जनसेवा के प्रति समर्पित नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने सादगी और प्रतिबद्धता से जनता के बीच पीपुल्स मैन की पहचान बनाई। उन्होंने बताया कि डोगरा छह बार विधायक दो बार सांसद और 26 वर्षों तक वित्त मंत्री रहे तथा राज्य के वित्तीय ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने युवाओं से डोगरा के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में युगल किशोर बाली, अनंत राम डोगरा, रमेश वर्मा, बी.एल. कंडले, भोला नाथ, राकेश शर्मा, विजय शर्मा, नरिंदर सिंह राठौर, डॉ. रमेश्वर शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

पीएसए के तहत हिस्ट्रीशीटर बाग हुसैन गिरफ्तार, भद्रवाह जेल भेजा

कठुआ, 17 जुलाई (हि.स.)। कठुआ पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त एक हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के तहत गिरफ्तार कर जिला जेल भद्रवाह भेज दिया है। जानकारी के अनुसार एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा आईपीएस के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए जिला मजिस्ट्रेट कठुआ के आदेश पर आरोपी बाग हुसैन उर्फ बग्गा पुत्र अली निवासी हरिया चक तहसील मढ़हीन के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। 17 जुलाई को थाना राजबाग की पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 8(1)(I) पीएसए के तहत वारंट तामील किया। आरोपी के खिलाफ जिला पुलिस कठुआ द्वारा प्रस्तुत डोजियर के आधार पर 16 जुलाई को आदेश जारी किया गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी एक हिस्ट्रीशीटर और आदतन अपराधी है। गिरफ्तारी के बाद उसे जिला जेल भद्रवाह में निरुद्ध कर दिया गया है।

पुलिस ने खनिजों के अवैध खनन व परिवहन के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई

पुंछ, 17 जुलाई (हि.स.)। अवैध खनन और पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी लगातार चल रही मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पुंछ जिला पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। सुरनकोट पुलिस स्टेशन द्वारा चलाए गए अलग-अलग अभियानों में पुलिस ने 10 वाहन और भारी मशीनें जब्त कीं । विश्वसनीय जानकारी के आधार पर खनिजों के अवैध खनन व परिवहन के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत सुरनकोट पुलिस स्टेशन की टीमों ने अपने अधिकार क्षेत्र में कई जगहों पर सघन चेकिंग और कार्रवाई अभियान चलाए। इन अभियानों के दौरान अवैध खनन गतिविधियों (खासकर नदी के किनारों से) में कथित तौर पर शामिल होने के कारण कुल सात डंपर, एक टिपर, एक जेसीबी मशीन और एक पोकलेन चेन मशीन जब्त की गईं। जब्ती के तुरंत बाद कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई शुरू करने के लिए खनन विभाग को सूचित कर दिया गया। अधिकारियों कहा कि अवैध खनन पर्यावरण, नदी के इकोसिस्टम और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। पुंछ जिला पुलिस ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है और जिले भर में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए नियमित रूप से कार्रवाई अभियान चलाती रहेगी।

घाटी के पंपोर गुड्स शेड पर पहली रेक की हैंडलिंग – माल एवं लॉजिस्टिक आवाजाही के लिए ऐतिहासिक क्षण

जम्मू, 17 जुलाई। उत्तर रेलवे, जम्मू मंडलद्व के लिए आज दिनांक 17 जूलाई को एक ऐतिहासिक दिन है। बारामूला-संगलदान रेल खंड पर स्थित पंपोर गुड्स शेड पर कश्मीर घाटी में पहली बार मालगाड़ी की हैंडलिंग सफलतापूर्वक की गई। सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद 15 जुलाई को प्रारंभ हुए इस गुड्स शेड पर 24 घंटे के भीतर ही पहली रेक का आगमन क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

यह अनंतनाग के बाद कश्मीर घाटी का दूसरा गुड्स शेड है, इस पहली हैंडलिंग ने यह सिद्ध कर दिया है कि नया शेड कश्मीर से और कश्मीर के लिए माल एवं लॉजिस्टिक आवाजाही में तुरंत प्रभावी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

पहली रेक से जुड़ी प्रमुख बातों पर ध्यान दें, तो पंपोर गुड्स शेड पर पहली रेक के माध्यम से सीमेंट की आवक की गई। यह रेक अंबाला मंडल के भारतगढ़ और किरतपुर साहिब से 21-21 BCN वैगन अल्ट्राटेक, ACC एवं अंबुजा सीमेंट लेकर पंपोर पहुंची। गुड्स शेड पर प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक बुकिंग एवं हैंडलिंग की सुविधा उपलब्ध है।

जम्मू कश्मीर क्षेत्र एवं जम्मू मंडल को होने वाले लाभ पर बात करें, तो पंपोर में गुड्स शेड के शुरू होने और पहली रेक की हैंडलिंग से कश्मीर घाटी को सीधे कई लाभ मिलेंगे।

पहला, अब घाटी के फल उत्पादकों, किसानों, सीमेंट एवं निर्माण सामग्री के व्यापारियों को अपना माल लाने-ले जाने के लिए अनंतनाग या अन्य दूरस्थ स्थानों पर निर्भर नहीं

रहना पड़ेगा। इससे समय और परिवहन लागत में भारी बचत होगी।

दूसरा, स्थानीय स्तर पर लोडिंग-अनलोडिंग, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग और अन्य सहायक सेवाओं में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

तीसरा, अनंतनाग गुड्स शेड पर दबाव कम होगा और माल की निकासी तेज एवं सुगम होगी। इससे कश्मीर से बाहर और बाहर से कश्मीर के अंदर माल की आवाजाही अधिक विश्वसनीय बनेगी।

चौथा, बेहतर माल ढुलाई से क्षेत्र में औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी और रेलवे के राजस्व में वृद्धि होगी। इस अतिरिक्त राजस्व का उपयोग यात्री सुविधाओं के विस्तार में किया जाएगा।

इस ऐतिहासिक अवसर पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, जम्मू श्री उचित सिंघल ने कहा कि पंपोर गुड्स शेड पर 24 घंटे के अंदर पहली रेक की हैंडलिंग जम्मू मंडल और कश्मीर घाटी के लिए गर्व का विषय है। यह शेड व्यापार जगत की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आज से कश्मीर की लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी एक नए युग में प्रवेश कर गई है। हमें विश्वास है कि यह शेड क्षेत्र के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

रेल प्रशासन ने सभी व्यापारिक संगठनों, उद्योगपतियों और आम जनता से अपील की है कि वे इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठाएं और मेक इन कश्मीर को बढ़ावा देने में रेलवे के साथ भागीदार बनें।

अमृत भारत स्टेशन योजना से रेलवे स्टेशनों को किया जा रहा आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित: सिंधिया

अशोक नगर, 17 जुलाई (हि.स.)। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के माध्यम से रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक सेवाएं मिलेंगी। इससे यात्रियों को उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्राप्त होंगी और रेलवे यात्रा अधिक सुगम बनेगी।

केन्द्रीय मंत्री सिंधिया शुक्रवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित मध्य प्रदेश के अशोक नगर रेलवे स्टेशन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे।

जेकेएएसीएल ने मैकाश कश्मीरी की जन्मशती पर संगीतमय कार्यक्रम आयोजित किया

जम्मू, 17 जुलाई। प्रख्यात कश्मीरी, हिंदी और उर्दू साहित्यकार **पंडित कैलाश नाथ कौल मैकाश कश्मीरीकी जन्मशती के उपलक्ष्य में जम्मू-कश्मीर कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी (जेकेएएसीएल) ने मैकाश कश्मीरी साहित्यिक सोसायटीके सहयोग से आज के. एल. सहगल हॉल, जम्मू में एक भव्य संगीतमय संध्या का आयोजन किया। कार्यक्रम में साहित्यकारों, कलाकारों, विद्वानों और मैकाश कश्मीरी के प्रशंसकों ने भाग लेकर उनकी समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को याद किया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जम्मू पश्चिम के विधायक अरविंद गुप्ता थे। अपने संबोधन में उन्होंने मैकाश कश्मीरी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे ऐसे महान साहित्यकार थे, जिनकी रचनाओं ने भाषा और संस्कृति की सीमाओं को पार किया। उन्होंने कहा कि मैकाश कश्मीरी जैसी महान विभूतियों की साहित्यिक और संगीत विरासत को युवा पीढ़ी तक पहुंचाना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे प्रयास समाज की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते हैं और युवाओं को अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देते हैं।

अरविंद गुप्ता ने अपने छात्र जीवन को याद करते हुए दीवान बद्रीनाथ (डीबीएन) स्कूल के सांस्कृतिक वातावरण की सराहना की और कार्यक्रम में विद्यालय के विद्यार्थियों की सहभागिता की प्रशंसा की।

इससे पहले जम्मू-कश्मीर कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी की अतिरिक्त सचिव सोनाली अरुण गुप्ता ने अतिथियों, कलाकारों और श्रोताओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अकादमी जम्मू-कश्मीर की समृद्ध साहित्यिक, कलात्मक और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

अमरनाथ यात्रा के 4600 से ज्यादा तीर्थयात्रियों का नया जत्था जम्मू से रवाना

जम्मू, 17 जुलाई (हि.स.)। कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार को अमरनाथ यात्रा के 4600 से ज़्यादा तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित गुफा मंदिर के दो बेस कैंपों के लिए रवाना हुआ।

अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह 4640 तीर्थयात्री जम्मू बेस कैंप से 171 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए जिनमें हल्की और भारी मोटर गाड़ियाँ शामिल थीं। इस जत्थे में बालटाल के लिए 1626 और पहलगाम के लिए 3014 तीर्थयात्री शामिल थे। वे कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था के तहत यात्रा के लिए रवाना हुए। यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से हो इसके लिए सिविल प्रशासन, पुलिस, सुरक्षा बलों और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने मिलकर इंतज़ाम किए थे।

अमरनाथ यात्रा ने सिर्फ़ 14 दिनों में 3 लाख का आंकड़ा पार करके एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वे कन्फर्म रजिस्ट्रेशन और तय तारीख पर ही यात्रा करें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन वाले किसी भी तीर्थयात्री को बेस कैंप तक जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी

जेपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक ने मरवाह और वारवान में ग्रिड कनेक्टिविटी एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति का लिया जायजा

किश्तवाड़, 17 जुलाई। जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेडके प्रबंध निदेशक गुरपाल सिंह ने आज मरवाह और वारवान घाटियों का व्यापक दौरा कर ग्रिड कनेक्टिविटी परियोजना तथा पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के तहत शेष गैर-विद्युतीकृत घरों तक बिजली पहुंचाने के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

दौरे के दौरान उन्होंने वारवान ब्लॉक के कवयार्ड, दासबल और इंशान तथा मरवाह ब्लॉक के अस्तान गाम, कादेरना और योरदू सहित विभिन्न परियोजना स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चल रहे कार्यों की समीक्षा की तथा फील्ड इंजीनियरों, कार्यान्वयन एजेंसियों और स्थानीय लोगों से बातचीत की।

प्रबंध निदेशक के साथ मुख्य अभियंता वितरण इंजीनियर अरशद हुसैन रेशी, मुख्य अभियंता परियोजनाएं इंजीनियर रविकांत कलसोत्रा सहित जेपीडीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी और कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

सामग्री की उपलब्धता, परिवहन और लाइन निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए गुरपाल सिंह ने कहा कि यह परियोजना इन दूरदराज क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके पूरा होने के बाद मरवाह और वारवान पहली बार मुख्य विद्युत ग्रिड से जुड़ेंगे, जिससे अलग-थलग बिजली प्रणालियों पर निर्भरता समाप्त होगी और लोगों को गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय तथा निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी।

यह कार्य जेपीडीसीएल के परियोजना विंग द्वारा आरडीएसएस के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसी एम/एस पीर पंजाल कंस्ट्रक्शंस प्रा. लिमिटेड, जेवी के माध्यम से 78.16 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से कराया जा रहा है। परियोजना के तहत मरवाह में 33/11 केवी, 2म6.3 एमवीए तथा वारवान में 33/11 केवी, 1म6.3 एमवीए क्षमता के रिसीविंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं।

डीसी सांबा ने नशा विरोधी अभियान की समीक्षा की, सख्त कार्रवाई, जनजागरूकता और पुनर्वास पर दिया जोर

सांबा, 17 जुलाई। उपायुक्त सांबा आयुषी सूदन ने आज जिला उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन (एनसीओआरडी) ढांचे के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिले में नशा विरोधी पहलों की समीक्षा की गई तथा मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए रणनीति को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने पिछली एनसीओआरडी बैठकों में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) की समीक्षा की तथा विभिन्न विभागों द्वारा प्रवर्तन, रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और जनजागरूकता के क्षेत्रों में हासिल प्रगति का आकलन किया। उपायुक्त ने समन्वित और परिणामोन्मुखी कार्यप्रणाली पर बल देते हुए सभी संबंधित विभागों को नशा तस्करी के

विरुद्ध कार्रवाई तेज करने तथा साथ ही रोकथाम और जनजागरूकता कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना सभी विभागों और संस्थानों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने सभी विभागों को सौंपे गए कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा अधिकारियों से कहा कि वे अपने कर्मचारियों को नियमित जागरूकता और परामर्श कार्यक्रमों के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों के प्रति संवेदनशील बनाएं। उन्होंने प्रत्येक सरकारी कार्यालय से नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए आयुषी सूदन ने स्वास्थ्य विभाग को जिला अस्पताल स्थित नशा उपचार केंद्र (एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी) को और सुदृढ़ बनाने, गुणवत्तापूर्ण उपचार, परामर्श और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं शिक्षा विभाग को शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों की क्षमता बढ़ाने के लिए नियमित जागरूकता एवं परामर्श कार्यक्रम आयोजित करने को कहा, ताकि नशे की चपेट में आने की आशंका वाले विद्यार्थियों की समय रहते पहचान कर उन्हें स्वस्थ एवं नशा मुक्त जीवन की ओर प्रेरित किया जा सके।

हरियाली की ओर कदम-कठुआ विधायक डॉ. भारत भूषण ने शुरू किया मेगा पौधारोपण अभियान

कठुआ, 17 जुलाई (हि.स.)। वन महोत्सव-2026 के तहत कठुआ में हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधायक कठुआ डॉ. भारत भूषण ने शुक्रवार को भव्य पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। यह अभियान रेडियो स्टेशन रोड स्थित कठुआ नहर के किनारे नीम का पौधा लगाकर शुरू किया गया। इस अवसर पर सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन कठुआ की डीएफओ हिताशी शर्मा, मॉर्निंग वॉकर ट्रस्ट के सदस्य, शहर के गणमान्य नागरिक और पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे और पौधारोपण में सक्रिय भागीदारी निभाई। विधायक डॉ. भारत भूषण ने बताया कि इस अभियान के तहत आंवला, अर्जुन, जामुन और बेल के कुल 101 पौधे लगाए गए। उन्होंने कहा कि यह पौधारोपण एक पेड़ मां के नाम और एक पेड़ शहीदों के नाम जैसे प्रेरणादायक अभियानों को समर्पित है जो समाज में पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ भावनात्मक जुड़ाव भी स्थापित करता है। उन्होंने आगे बताया कि पौधों और ट्री गार्ड के लिए आवश्यक धनराशि उनके द्वारा विधायक निधि से उपलब्ध करवाई गई है ताकि कठुआ का हरित क्षेत्र बढ़ाया जा सके और ग्रीन कठुआ क्लीन कठुआ के लक्ष्य को साकार किया जा सके।

इस मौके पर प्रो. राम मूर्ति शर्मा, गुर परशाद खजूरिया, कमल शर्मा, ललित अग्रवाल, राजिंदर गुप्ता, अशोक शर्मा, उपदेश अंडोत्रा, प्रेम नाथ डोगरा, राहुल देव, इंदु रेखा, नागेश कुमार, विनोद कुमार, देव राज, रविंदर पठानिया, शिंगारा सिंह, राजिंदर सिंह बंटी, करण सिंह, अशोक जसरोटिया, शशि पाल शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने पौधारोपण किया। विधायक ने कहा कि बरसात के मौसम में ऐसे और भी पौधारोपण अभियान आम नागरिकों के सहयोग से आयोजित किए जाएंगे, ताकि पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का रूप दिया जा सके।

Union Territory of Jammu and Kashmir
Office of the Executive Engineer, Mechanical & Hospital Division Udhampur

NOTICE INVITING TENDER

For and on behalf of Lt. Governor, of Jammu & Kashmir (UT) e-tenders are invited in two cover system, from reputed and registered firms for the job mentioned below:-

S.No.	Description of work	N.I.T No	Estimated/ Approved Cost (in Lacs)	Earnest Money/ Performance Security	Cost of tender documents	Time of completion	Eligibility Criteria of Bidder	Project Indenting Authority	Tender Receiving Authority
01	Day to Day Maintenance of Assets Like Electrical and Mechanical Appliances, Plumbing and Daily Usable Items Required for Snow Clearance Hut at Patnitop.	E-NIT No. MHDU/TS/ 21 of 2026-27 Dt: -16/07/2026 Due on:- 27/07/2026	2.25 Lac	Earnest Money 2% of estimated amount, amounting to Rs. 4500/- only shall be submitted by all Participating Bidder in the shape of CDR/FDR/TDR/BG. Performance Security 3% of the contract value shall be submitted by the lowest Bidder before the allotment of work order in the shape of CDR/FDR/TDR	Rs. 200/- (Fixed Amount) in the shape of challan through J&K Govt. Treasury indicating treasury Voucher No. & date and also indicating the name of work duly credited to MH-0059(PWD) Misc. Revenue and uploading a copy of treasury challan/receipt on e-tendering portal OR The bidder may deposit tender fee in shape of e-challan through Account No. 002801020000009, J&K Bank, Udhampur, of Executive Engineer Mechanical Division Udhampur)	20 (Twenty days)	Registered/ Reputed / Mechanical firms having sufficient experiences for the similar nature work	Departmental work	Executive Engineer Mechanical & Hospital division Udhampur

Position of Funds:-(Available)
Position of AA/Tech. Sanction:-(Accorded)
The e-NIT consisting of qualifying information, eligibility criteria, specifications, terms & conditions, Bill of Quantities can be seen / down-loaded from the J&K govt. website www.jktenders.gov.in(Tender ID 2026_PWDJK_316274_1)
No: MHDU/TS/1067
Dated:- 16-07-2026

DIP/J-6022/26
Dtd: 17-7-2026

-sd-
(Er.Vaneet Nanda)
Executive Engineer
Mechanical & Hospital Division
Udhampur

संपादकीय

सरकार को सार्थक हस्तक्षेप करना चाहिए

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए केंद्र सरकार को इस मामले का संज्ञान लेते हुए सार्थक हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार को ऐसा समाधान तलाशना चाहिए जिससे विश्वप्रसिद्ध शिक्षाविद्, नवोन्मेषक और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक का आंदोलन समाप्त हो सके। वांगचुक ने अपने कार्यों के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उल्लेखनीय है कि उनकी स्वास्थ्य निगरानी कर रहे डॉक्टरों के अनुसार, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 19 दिनों के दौरान उनका वजन 9 किलोग्राम से अधिक कम हो चुका है। चिकित्सकों ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक उपवास के कारण उनकी स्थिति अब गंभीर हो गई है और इसका असर उनके आंतरिक अंगों पर भी पड़ सकता है। स्थिति को और गंभीर इस बात ने बना दिया है कि राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और समर्थकों की अपीलों के बावजूद वांगचुक अपना अनशन समाप्त करने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया मिले बिना अनशन तोड़ना गलत संदेश देगा।

वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील करने वालों में डॉ. करण सिंह भी शामिल हैं। उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा कि देश ऐसे प्रतिभाशाली नवोन्मेषक को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता, जिसने वर्षों से लद्दाख के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा संगीतकार विशाल ददलानी, अभिनेता सयाजी शिंदे और लेखिका शोभा डे ने भी सरकार से वांगचुक के साथ संवाद शुरू करने की अपील की है और उनकी बिगड़ती सेहत पर चिंता व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वांगचुक के स्वास्थ्य की प्रतिदिन निगरानी की जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर तत्काल चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का जीवन अमूल्य है।

इसके जवाब में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि उन्हें वांगचुक के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण पर कोई आपत्ति नहीं है। यह कदम सराहनीय है, लेकिन इससे भी अधिक आवश्यक यह है कि केंद्र सरकार वांगचुक के साथ सार्थक संवाद शुरू करे, उन्हें अनशन समाप्त करने के लिए राजी करे और बातचीत के माध्यम से देश में प्रश्नपत्र लीक (पेपर लीक) जैसे गंभीर मुद्दे पर विचार-विमर्श करे।

उल्लेखनीय है कि सीजेपी जंतर-मंतर पर कथित नीट परीक्षा अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहा है। संगठन ने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन, 20 जुलाई को संसद मार्च का भी आह्वान किया है।

सरकार को यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। साथ ही यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि सोनम वांगचुक का जीवन अत्यंत मूल्यवान है। इसलिए सरकार को उनकी जान बचाने और इस गतिरोध का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए सक्रिय एवं सकारात्मक पहल करनी चाहिए।

ब्रिक्स देशों में पोषण संवर्धन के लिए खाद्य भंडार

डॉ. स्वाति नायक

भारत में उभरती हुई भंडार प्रणालियाँ यह दिखाती हैं कि भंडार केवल जमा किए गए अनाज से कहीं ज़्यादा सक्रिय पोषण प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक भंडारण, डिजिटलीकरण, विकेंद्रीकरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ाव की प्रक्रिया प्रमुख अनाज - चावल और गेहूं - के साथ-साथ दालों, मोटे अनाजों और पोषण वर्धित खाद्य पदार्थों की जैविकपोषण वर्धित किस्मों को शामिल करके भंडार में विविधता लाने का मौका देती है।यह और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत दुनिया के पोषण परिदृश्य में फसल विविधीकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है।

जलवायु से जुड़ी चुनौतियों और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान अक्सर वैश्विक खाद्य अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, जिससे ब्रिक्स समूह को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। खाद्य भंडारों, जिन्हें अक्सर आपातकालीन स्टॉक के रूप में देखा जाता है, कोअब पोषण सुदृढ़ता, स्थिरता और तेज़ी से बदलती बाजार और सामाजिक प्रणालियों के हिसाब से नए सिरे से व्यवस्थित करने की ज़रूरत है।

हालांकि वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए रणनीतिकभंडार बनाए रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी सवाल यह है कि जलवायु और व्यापार की अनिश्चितताओं के साथ-साथ भूख और कुपोषण की लगातार मौजूद समस्याओं के जवाब में किस तरह के भंडार निर्मित किये जाने चाहिए। विश्व बैंक-एफएओ-डब्ल्यूएफपी रिपोर्ट (2025) - खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए रणनीतिक अनाज भंडार को मजबूत करना - में बताया गया है कि 2024 में 74 देशों में 343 मिलियन लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे थे। यह संख्या कोविड-19 महामारी से पहले के सालों में खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या से लगभग दोगुनी है। बहु-स्तरीय आर्थिक उथल-पुथल से व्यापार में व्यवधान हुए हैं और भूख में वृद्धि हुई है, इन सभी ने खाद्य सुरक्षा के लिए नए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।

2026 में हालात और भी खराब हो गए। विश्व बैंक के अनुसार, पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए तेल और उर्वरक का परिवहन प्रभावित हुआ है, जो वैश्विक कृषि-खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। फरवरी से मार्च 2026 के बीच उर्वरकों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई, जिसमें यूरिया की कीमत एक ही महीने में लगभग 46 प्रतिशत बढ़ गई। विश्व खाद्य कार्यक्रम के पूर्वानुमानों के अनुसार, लगातार व्यवधान के कारण 45 मिलियन तक लोग भुखमरी की स्थिति में पहुंच सकते हैं।

यह ब्रिक्सदेशों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इनमें से अधिकांश देश प्रमुख कृषि उत्पादक/आयातक और उर्वरक के उपभोक्ता दोनों हैं।

हालाँकि, खाद्य भंडारों के बारे में पारंपरिक सोच अब पुरानी पड़ती जा रही है। पारंपरिक रूप से, खाद्य भंडार बनाने का उद्देश्य मुख्य रूप से कीमतों को स्थिर रखना या अस्थायी कमी से निपटना था। दूसरी ओर, आधुनिक समस्या अधिक जटिल है और इसके लिए ऐसे उपायों की जरूरत है जो न सिर्फ पर्याप्त कैलोरी की गारंटी दें, बल्कि खाद्य के पोषण संतुलित होने, किफायती होने और व्यवधानों के बीच लगातार उपलब्ध होने की भी गारंटी दें। यूरोपीय आयोग की संश्लेषण रिपोर्ट - विकासशील देशों में खाद्य और पोषण सुरक्षा बढ़ाने के लिए खाद्य भंडार का उपयोग - के अनुसार, खाद्य और पोषण सुरक्षा; अनाज की भौतिक उपलब्धता से कहीं अधिक है।

ब्रिक्स देशों के संदर्भ में यह परिवर्तन और भी महत्वपूर्ण बन गया है, जहाँ भरपूर खाद्य संसाधन होने के बावजूद भी खाद्य संकट बरकरार है। उदाहरण के तौर पर, भारत ने 2024 से 2025 की अवधि में रिकॉर्ड 353.96 मिलियन टन अनाज का उत्पादन किया है, साथ ही दुनिया के सबसे बड़े खाद्य नेटवर्क में से एक को बनाए रखा है। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय द्वारा फसल से घर तक- अनाज भंडारण के लिए सुदृढ़ अवसंरचना का निर्माण विषय पर 2025 में जारी एक पृष्ठभूमि विज्ञप्ति में इस तथ्य का उल्लेख किया गया था।

भारत में उभरती हुई भंडार प्रणालियाँ यह दिखाती हैं कि भंडार केवल जमा किए गए अनाज से कहीं ज़्यादा सक्रिय पोषण प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक भंडारण, डिजिटलीकरण, विकेंद्रीकरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ाव की प्रक्रिया प्रमुख अनाज - चावल और गेहूं - के साथ-साथ दालों, मोटे अनाजों और पोषण वर्धित खाद्य पदार्थों की जैविकपोषण वर्धित किस्मों को शामिल करके भंडार में विविधता लाने का मौका देती है।यह और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत दुनिया के पोषण परिदृश्य में फसल विविधीकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है।

इसी तरह, चीन भी अपने भंडारों को लेकर अपनी रणनीति को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसे दृष्टिकोण के तहत, जो उसके खाद्य प्रणाली में सुदृढ़ता को ध्यान में रखता है। चावल, गेहूँ और मक्का का भारी स्टॉक जमा करने के साथ-साथ, बीजिंग अब स्मार्ट भंडारण, एआई-समर्थित खाद्य निगरानी, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स और देसी बीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। अब खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में पोषण के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करने पर अधिक ध्यान है, ताकि फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और विविध आहार प्राप्त किए जा सकें।

रूस ने जो रास्ता अपनाया है, वह भंडार नीति के एक और पहलू का उदाहरण पेश करती है। यह भू-राजनीतिक सुदृढ़ता है। रूस ने खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच स्पष्ट संबंध बनाए हैं, अपने भंडार बढ़ाए हैं, कृषि क्षेत्र के लिए घरेलू उत्पादन पर ध्यान दिया है तथा पश्चिम एशिया और अफ्रीका में अनाज निर्यात और उर्वरकों का भू-राजनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग किया है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ प्रतिबंध, अलग-अलग व्यापारिक संबंध और निर्यात नियंत्रण आम होते जा रहे हैं, यह एक महत्वपूर्ण बात है।

एक और उदाहरण मौजूद है जो अपने आप में बहुत अहम है - दक्षिण अफ्रीका। संपूर्ण खाद्य उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय, दक्षिण अफ्रीका की समस्याओं को अनाज की किफायती कीमत और पोषण तक पहुँच की कमी के रूप में देखा जा सकता है। इस मामले में, सरकार का ध्यान पोषण-संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा, स्कूलों में खाना खिलाने की योजनाओं,सरकारी खरीद और सामुदायिक खाद्य प्रणालियों मौसम के असर से सुरक्षित बनाने पर जाता है। ऐसी स्थिति में,भंडार अधिकतर व्यापक अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के साधन के बजाय पोषण कार्यक्रमों को लागू करने का एक उपकरण बन जाते हैं।

इसके अलावा, विश्व बैंक-एफएओ-डब्ल्यूएफपी रिपोर्टइस बात पर जोर देती है कि रणनीतिक भंडार तब सबसे प्रभावी होते हैं, जब वे 卐छोटे, सरल और स्मार्ट卐 होते हैं और बाज़ार प्रबंधन केबजाय अधिकतर आपातकालीन प्रतिक्रिया पर केंद्रित होते हैं। इसी तरह, यूरोपीय आयोग की रिपोर्ट बताती है कि भंडार का स्तर तो मायने रखता ही है, लेकिन असल में शासन ही यह तय करती है कि भंडार खाद्य सुरक्षा नीति के लक्ष्यों में मदद करेंगे या उन्हें नुकसान पहुँचाएँगे।

यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका प्रभाव 'ब्रिक्स देश अपनी खाद्य सुरक्षा स्थिति में सुधार करने के लिए कैसे सहयोग कर सकते हैं' पर पड़ता है। कई देशों के साझा भंडार निर्मित करने के बजाय, जिन्हें बनाना राजनीतिक रूप से मुश्किल और लॉजिस्टिक्स के लिहाज़ से असंभव है, ब्रिक्स के लिए एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय तालमेल प्रणाली का निर्माण बेहतर हो सकता है, जो डेटा आदान-प्रदान, समन्वित इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, शुरुआती चेतावनी प्रणाली, सरकारी खरीद मानक नियम और भंडारण अवसंरचना को बेहतर बनाने पर केंद्रित हो।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भंडार के भविष्य को पोषण संबंधी विविधता से जोड़ा जाना चाहिए। मुख्य रूप से चावल और गेहूं पर आधारित भंडार छिपी हुई भूख और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के बढ़ते खतरे का सामना नहींकर पाएँगे। स्वस्थ/पोषक तत्वों से भरपूर चावल और गेहूं, जैसे जैविक पोषण वर्धित चावल/गेहूं, दालें, मोटे अनाज और पोषण वर्धित अनाज जैसी चीज़ों का एक विविध मिश्रण सुनिश्चित करने की ज़रूरत है।इससे ब्रिक्स देशों के लिए अपने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों को सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जोड़ना संभव होगा।

भंडारों की योजना बनाते समय जलवायु के हिसाब से सुदृढ़ता सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है। बाढ़, सूखा, चक्रवात और लू जैसी घटनाओं के बार-बार होने के कारण, यहसुनिश्चितकरना ज़रूरी हो गया है कि इन आपदाओं का असर उत्पादन और भंडारण, दोनों प्रक्रियाओं पर एक साथ न पड़े। इस संदर्भ में, आधुनिक भंडारों के लिए सिर्फ पारंपरिक भंडारों में निवेश करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्किकोल्ड चेन, अलग-अलग जगहों पर बनी भंडारण सुविधाओं, आई-ओ-टी सक्षम निगरानी प्रणालियों और नमी नियंत्रण प्रणालियों में भी निवेश करना जरूरी हो गया है।

दुनिया की खाद्य भंडारण नीति को बदलने में मदद करने के लिए ब्रिक्सदेश सबसे अछी स्थिति में हैं। सामूहिक रूप से, वे दुनिया के अनाज उत्पादन, उर्वरक उपयोग, कृषि व्यापार और जोखिम में रहने वाले समुदायों के मामले में में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सही योजना के साथ, उनकी भंडारण सुविधाओं को केवल आपातकालीन व्यवस्था के स्थान पर सुरक्षित पोषण, मौसम में बदलाव का सामना करने और भू-राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने वाली प्रणाली में बदला जा सकता है।

भविष्य के खाद्य भंडार की सफलता केवल उनके भंडारण सुविधा में रखे अनाज की मात्रा पर निर्भर नहीं करेगी। इसके बजाय, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वे संकट के समय समाज को स्थिर रखने में कितनी मदद कर सकते हैं, गरीब लोगों के लिए अछे पोषण के परिणाम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, क्षेत्रीय खाद्य उत्पादन प्रणाली को कैसे मजबूतकर सकते हैंऔर कमजोर वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता को किस प्रकार कम कर सकते हैं। इसलिए, ब्रिक्स देशों के लिए खाद्य भंडार का सवाल यह नहीं होना चाहिए कि अधिक भोजन कैसे पैदा करें, बल्कि यह होना चाहिए कि स्मार्ट, पोषण-केंद्रित भंडार कैसे बनाए जाएं।

(लेखिका सीड सिस्टम्स और प्रोडक्ट मैनेजमेंट की दक्षिण एशिया प्रमुख तथा इंडिया कंट्री मैनेजर (अंतरिम) हैं नॉर्मन बॉरलॉग फील्ड पुरस्कार विजेता (विश्व खाद्य पुरस्कार) 2023, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान।)

अमेरिकी व्यावसायिक सैन्य शिक्षा और वैश्विक रणनीति

सैयद सुलेमान अख्तर, अमेरिकी दूतावास

जब हम सैन्य प्रशिक्षण के बारे में सोचते हैं, तो अकसर हमारे मन में कीचड़ से भरे प्रशिक्षण शिविरों में शारीरिक अभ्यास या राइफल ड्रिल करते कैडेटों की तस्वीर उभरती है। हालांकि, सैन्य शिक्षा का एक और पहलू भी है—कक्षा, जहां व्यावसायिक सैन्य शिक्षा के अभिन्न हिस्से के रूप में बड़ी मात्रा में बौद्धिक तैयारी होती है। रक्षा विश्लेषक रामकृष्ण रमानी ने हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग के आईवीएलपी कार्यक्रम वी द पीपल- मिलिट्री एजुकेशन इन अमेरिका के दौरान इन संरचनात्मक ढांचों का अध्ययन किया। रमानी चेन्नई स्थित एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मद्रास विश्वविद्यालय में रक्षा और रणनीतिक अध्ययन पढ़ाते हैं।

उन्होंने इस अवसर का उपयोग अमेरिकी व्यावसायिक सैन्य शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम निर्माण और संस्थागत संबंधों का अध्ययन करने के लिए किया। उन्होंने विशेष व्यावसायिक सैन्य शिक्षा संगोष्ठियों में भाग लिया। व्यावहारिक युद्धाभ्यास सत्र में शामिल हुए और कई शहरों में सैन्य शिक्षा विशेषज्ञों तथा सरकारी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। वह कहते हैं, सभी पेशेवर सेनाओं की तरह, अमेरिका में भी व्यावसायिक सैन्य शिक्षा एक ऐसा करियर-व्यापी क्रम है, जिसे सामरिक विशेषज्ञों को रणनीतिक विचारकों में बदलने के लिए तैयार किया गया है। वह कहते हैं, यह प्रणाली रणनीतिक सोच को एक ऐसे कौशल के रूप में देखती है, जिसे लगातार निखारने की आवश्यकता होती है। इसलिए कक्षा सत्र किसी अधिकारी के काम का मुख्य हिस्सा होते हैं, कोई अतिरिक्त गतिविधि नहीं।

यह व्यापक शिक्षा प्रारंभिक स्तर से ही शुरू हो जाती है, जिसमें विद्यार्थियों को सक्रिय सैन्य सेवा में प्रवेश करने से काफी पहले रणनीतिक ढांचों से परिचित कराया जाता है। रमानी ने इसका प्रत्यक्ष अनुभव पेंसाकोला हाईस्कूल और कलैराडो मिलिट्री अकादमी में किया। यह दोनों संस्थान एयर फोर्स जूनियर रिजर्व ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स की मेजबानी करते हैं। यह अमेरिकी सशस्त्र बलों द्वारा पूरे अमेरिका के हाई स्कूलों में प्रायोजित एक फेडेरल कार्यक्रम है। रमानी बताते हैं, ग्रेड 8 और उससे ऊपर के छात्रों को परेड ड्रिल के अलावा बुनियादी सैन्य विज्ञान, इतिहास, विश्व मामलों की मूल बातें और ड्रोन निर्माण व संचालन, उपग्रह नेविगेशन जैसी प्रासंगिक तकनीकों से परिचित कराया जाता है।

रमानी कहते हैं, आमतौर पर युवा हाईस्कूल ग्रेजुएट वेस्ट प्वाइंट जैसे सेवा अकादमियों में प्रवेश करते हैं या कॉलेज के विद्यार्थी रिजर्व ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स में शामिल होते हैं। जैसे-जैसे अधिकारी रैंक में ऊपर बढ़ते हैं, शिक्षा प्रणाली भी अपना स्वरूप बदलती है। शुरुआती वर्षों में ध्यान सामरिक और क्षेत्र-आधारित प्रशिक्षण पर रहता है।

किसान और गांव को आत्मनिर्भर बनाने की चुनौती

मनोज कुमार मिश्र

अस्सी के दशक के आखिर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का कम पढ़े-लिखे और खांटी किसान चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत की अगुवाई में भारतीय किसान यूनियन के नाम से अराजनैतिक एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ जिससे लखनऊ और दिल्ली की सरकारें हिल गई। विभिन्न कारणों से वह आंदोलन कुछ सालों में कमजोर होकर दम तोड़ दिया। जिन सवालों पर वह आंदोलन शुरु हुआ और उसे भारी समर्थन मिला, वे सवाल आज भी वहीं खड़े हैं। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने अपने शासन के 12 साल में समाज के हर वर्ग के साथ गांव और किसान को आत्मनिर्भर बनाने के हर प्रयास किए हैं। किसान हित में 2021 में तैयार किए तीन कानून विपक्ष के सुनियोजित विरोध के चलते भारी बहुमत होते हुए किसान हित में वापस लिया। इतना ही नहीं हर साल इसमें नई योजनाओं को शामिल करके और बेहतर काम किए जा रहे हैं। चौधरी टिकैत अपने आंदोलन को अराजनैतिक मानते हुए भी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को अपना आदर्श मानते थे। आंदोलन के दौरान कुछ बातें दोहराते रहते थे। उसका उल्लेख जरूरी है। वे कहते थे कि किसान अकेली ऐसी कौम है जो ज्यादा उत्पादन करके भी रोती है और कम उत्पादन करके भी। कम उत्पादन में लागत नहीं निकली और ज्यादा उत्पादन में सही दाम नहीं मिलता। उसी तरह हर उत्पादन करने वाला अपने उत्पाद का दाम खुद तय करता है लेकिन किसान के दाम को वे तय करते हैं, जिन्होंने जीवन में कभी खेती की नहीं। वे चौधरी चरण सिंह के मुख्यमंत्री रहते यानी 1967 में जितने गेहूं या गन्ना में जितना सोना मिलता था, उससे थोड़ा कम दाम तय करने की मांग करते रहे।

किसानों की माली हालत सुधारने का यह एक फार्मूला तो यह हो सकता है लेकिन पूरा समाधान इससे भी नहीं हो सकता है। अब हालात बदल गए हैं। सरकार ने गांवों को समृध बनाने के लिए देश के सालाना बजट में भारी बढ़ोतरी की। 2014 में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार केन्द्र में आने से पहले कृषि का बजट 27,663 करोड़ रुपये था, अब वह बढ़कर 1 लाख 40 हजार करोड़ हो चुका है। आज भी देश के 81 करोड़ लोगों को हर महीने फ्री अनाज दिया जा रहा है। सरकार के प्रयास से 58 करोड़ जन-धन खाता खुला है। चार करोड़ पक्के मकान बने। 12 करोड़ शौचालय बने। 16 करोड़ घरों में नल से जल दिया गया। 11 करोड़ लोगों को रसोई गैस कनेक्शन दिए गए। किसान सम्मान निधि के तहत 4.3 लाख करोड़ रुपये दिए गए। 22 फसलों के समर्थन मूल्य में 71 फीसदी की बढ़ोतरी की गई। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना(मनरेगा) अब वीबी जीरामजी योजना बन गई है। उस योजना में 26 करोड़ लोग पंजीकृत हैं, जिन्हें 125 दिन का रोजगार दिया जाता है। हर तरह के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। यूरिया पर 90 फीसदी सब्सिडी दी गई है। फसल बीमा योजना लागू की गई है। किसानों को आसानी से कर्ज दिलवाने की व्यवस्था की गई हैं। सिंचाई के साधन बढ़े हैं। किसानों और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी योजनाओं की लंबी सूची है।

बावजूद इसके ने तो निचले स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार कम हुआ और न ही गांवों से पलायन रुका। सरकार ने लाभार्थियों का बैंक खाता खुलवाकर सीधे पैसा उसके खाते में भेजने का इंतजाम किया तो भ्रष्टाचार करने वाले बाहर से ही सौदेबाजी करने लगे। एक ही शौचालय के साथ अनेक फोटो खिंचवाकर कमीशन देकर भुगतान पाने लगे। इस भ्रष्टाचार के चलते बिना रिश्वत कम ही आवास बने और दूसरी सुविधाएं लोगों को दी गई। मनरेगा का भ्रष्टाचार तो पहले से ही जग जाहिर है। भाजपा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(राजग) की सरकार के प्रयास से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, उसमें कमी आई है। इन सभी से बड़ी समस्या बार-बार मानसून का धोखा देना और फसल की सरकार से सही मायने में खरीद की गारंटी न मिलना है। इस बार फिर बरसात दगा दे रही है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि में कम बरसात होने से धान की रोपाई देरी से हो रही है। इतना ही नहीं वही किसान रोपाई कर पा रहे हैं, जो सक्षम हैं। यानी जिनके परिवार का कोई और व्यवसाय है या परिवार में कोई नौकरी पेशा है। कम बरसात से दलहन और कपास की खेती पर भी असर पड़ा है। यही हाल सब्जियों का है।

सरकार के प्रयास और दावों के बावजूद कब तक देश भर के किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और अपनी फसल का लाभप्रद मूल्य मिलेगा। कब तक किसानी का काम लाभकारी बन जाएगा और बेकारी, भुखमरी और गरीबी के चलते गांवों से होने वाला पलायन कम होगा। मनरेगा के चलते तमाम भ्रष्टाचार होते हुए बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मिले और कोरोना संकट के दौरान बंटे बड़े पैमाने पर चावल-गेहूं से भुखमरी रुकी। सरकार को यह योजना ज्यादा उपयोगी लगी, इसलिए इसे अब तक जारी रखा गया है।

गांव में रहने वाले खेतिहर मजदूरों की समस्या अलग तरह की है। सरकारी योजनाओं का उन्हें भले ही भ्रष्टाचार के चलते पूरा लाभ भले ही नहीं मिलता है लेकिन उससे उनके आर्थिक हालात में कुछ सुधार हुआ है। बड़ी तादाद में खेतिहर मजदूरों ने अपेक्षाकृत संपन्न राज्यों में मजदूरी करके अपनी आर्थिक हालात में सुधार किया। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अब वीबी जीरामदी के बजट में हर साल बढोतरी हो रही है। इस योजना का इस साल का बजट 1.50 लाख करोड़ सालाना तय किया गया है। बड़ा संकट छोटे किसानों के लिए है, जिनके लिए खेती जानलेवा बनती जा रही है। एक अनुमान के अनुसार देश के 85 फीसद से ज्यादा किसानों के पास ढ़ाई एकड़ से कम जमीन है। इन किसानों पर सरकारी योजनाओं का ज्यादा फोकस होना चाहिए। देश के सात लाख से ज्यादा गांवों को यही किसान आबाद किए हुए हैं। इन्हीं के बूते कोरोना संकट के दौरान भी देश में अन्न की कमी नहीं हो पाई।

विपक्ष के सुनियोजित किसान आंदोलन जिन तीन कृषि कानूनों को खत्म करवाने के लिए शुरू किया गया था उनमें एक कानून मंडियों के बाहर भी उपज बेचने की इजाजत देने से था। दूसरा कानून किसानों को सहकारी खेती की अनुमति देने वाला और तीसरे में अनिवार्य फसलों पर से रोक हटाने का था (1.कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य(संवर्धन व सरलीकरण) कानून-2020,2. कृषक(सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर कानून-2020 और 3. आवश्यक वस्तु(संशोधन) कानून-2020)। सरकार यह समझाती रही कि इन बिलों से किसानों को केवल लाभ ही होगा। उनकी जमीन कोई नहीं ले सकता और मंडियां खत्म नहीं की जाएगी। फसलों को खुले में बेचने की इजाजत दी जाएगी। देश में मंडी और उसमें सक्रिय आढ़तियों की व्यवस्था पंजाब और हरियाणा में ही सबसे मजबूत है। पंजाब से ही कुछ किसानों का जत्था दिल्ली की एक सीमा सिंधु बार्डर पर इन कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए आंदोलन शुरू किया। उनके साथ हरियाणा के किसान भी जुड़े। फिर टिकरी बार्डर और गाजीपुर बार्डर पर आंदोलन चलने लगा। कुछ ही दिनों में आंदोलन सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का सुनियोजित षड़यंत्र बन गया।

11 दौर की बातचीत में समाधान नहीं निकला और सरकार को लगा कि उसे सुनियोजित तरीके से किसान विरोधी साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिलों को वापस लेने की घोषणा की और 2012 के संसद के शीतकालीन सत्र में उसे वापस ले लिया गया। एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) किसानों को दिलाने के लिए किसान संगठनों के साथ कमेटी बनाना तय किया गया। आंदोलन में शुरू से ही जमकर राजनीति होने लगी थी। इसलिए यह आंदोलन भी कामयाब न बन पाया। इस आंदोलन के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार दूसरी बार बहुमत में आ गई। यही हाल चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत की अगुवाई वाली भारतीय किसान यूनियन का हुआ था। वह तभी तक ताकतवर रहा जब तक वह सक्रिय राजनीति से दूर रहा और आंदोलन अहिंसक रहा। वह आंदोलन भी अन्य मुद्दों के अलावा किसानों पर से सीमित इलाके में फसल बेचने पर रोक के विरोध में था। वह आंदोलन तब तक सफल रहा जब तक केवल किसानों का रहा। जैसे ही राजनीतिक दल किसानों का समर्थन पाने के लिए उन्हें अपने पक्ष में करने में लग गए, आंदोलन भटक गया। यहां तक कि चौधरी टिकैत का कैंसर जैसी घातक बीमारी से 2011 में एक तरह से गुमनाम निधन हुआ।वास्तव में अन्य व्यवसाय करने वालों की तरह किसानों को ऊंची कीमत पर अपनी फसल बेचने की आजादी मिलनी ही चाहिए। यह संभव कब और कैसे होगा, इसका जवाब आसान नहीं है। बड़ी समस्या तो ढाई एकड़ से कम जोत वाले देश के 85 फीसद किसानों की है जिनका हर तरह से शोषण होता आया है। उनके पास अपने फसल को मंडी तक ले जाने के साधन नहीं हैं और न ही फसल को कुछ समय तक सुरक्षित रखने के लिए भंडार। वे तो गांव से लेकर मंडी तक आढ़तियों या बिचौलियों के शोषण झेलने को मजबूर हैं। अगर चार-पांच किसान मिलकर किराए की गाड़ी से अपने उत्पाद मंडी में लेकर पहुंच भी जाएं तो वहां सक्रिय बिचौलियों को पता है कि वे विपन्न हैं उनके पास कुछ दिन इंतजार करने के साधन नहीं हैं, तो वे उन्हें किसी भी दाम पर अपने फसल को बेचने के लिए मजबूर कर देते हैं। इतना ही नहीं उन्हें अगली फसल के लिए पैसों की जरूरत है। उनके घर का हर काम उसी फसल की बिक्री पर निर्भर है। केन्द्र की सरकार इस हालात को बदलने के प्रयास में लगी है। इसीलिए स्वामीनाथन आयोग ने एमएसपी तय करने के लिए समग्र लागत से पचास फीसद जोड़कर दाम तय करने का सुझाव दिया। अभी कुल 23 उत्पादों के लिए ही न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) तय होता है। जबकि बड़ी तादाद में किसान फल, सब्जी, दूध, अंडा, मछली आदि डेयरी उत्पाद का उत्पादन करते हैं। इसलिए अब सरकार को एमएसपी में शामिल उत्पादों की संख्या बढ़ानी चाहिए। सबसे बड़ी जरूरत यह है कि यह गारंटी मिलनी चाहिए कि एमएसपी से कम दाम पर खरीदने वाले को सजा मिलेगी। केन्द्र सरकार यह दावा करती रही कि मंडी बंद नहीं हो रही होगी। इसके साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित करें कि हर गांव-गांव खरीद केन्द्र काम करेंगे ताकि छोटे किसानों को अपने फसल के वाजिब दाम के लिए दर-दर की ठोकर नहीं खानी पड़े। सही मायने में सभी किसानों की आर्थिक हालत तभी सुधरेगी जब सरकार चौतरफा प्रयास करेगी। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का उपाय कर रही है लेकिन उसका पूरा लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, बैंकों से सस्ते दर पर कर्ज मिलने की व्यवस्था, कृषि उत्पाद को देश के विभिन्न इलाकों में पहुंचाने के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाने आदि तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिससे छोटे किसानों को काफी मदद मिल रही है। सबसे बड़ी समस्या इन योजनाओं का हर जरूरतमंद तक पहुंचाने और कृषि क्षेत्र में उन प्रयासों को करने से है जिससे किसानों की आमदनी बढ़े। कृषि उत्पाद से जुड़े लाभकारी उद्योगों को गांव-गांव तक पहुंचाने की है। सरकार प्रयास तो कर रही है लेकिन यह काम बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है।

(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

ओरिएंटल कप में जीडी गोयनका स्कूल और भारती पब्लिक स्कूल बने चैंपियन

एजेंसी

नई दिल्ली। एक सप्ताह तक चले रोमांचक मुकाबलों के बाद ओरिएंटल कप 2026 फुटबॉल टूर्नामेंट के चौथे संस्करण का शानदार समापन डॉ. अंबेडकर स्टेडियम में लड़कों और लड़कियों के फाइनल मुकाबलों के साथ हुआ। जीडी गोयनका स्कूल, द्वारका ने लड़कों के वर्ग का अपना पहला ओरिएंटल कप खिताब जीता, जबकि भारती पब्लिक स्कूल ने लड़कियों के वर्ग में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। दोनों टीमों ने पहली बार ओरिएंटल कप का खिताब जीतकर टूर्नामेंट के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफियों के साथ आकर्षक नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। लड़कों और लड़कियों दोनों वर्गों की विजेता टीमों को डेढ़ लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी गई, जबकि उपविजेता टीमों को 75 हजार रुपये प्रदान किए गए। इसके अलावा, विजेता और उपविजेता टीमों के कोचों को भी उनके योगदान के लिए क्रमशः 50 हजार और 25 हजार रुपये की नकद राशि देकर सम्मानित किया गया। लड़कों के वर्ग में जीडी गोयनका स्कूल, द्वारका के कार्तिकेय कश्यप चुघ और लड़कियों के वर्ग में मॉडर्न स्कूल की ध्वनि बिदादा टूर्नामेंट की सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी रहीं। पूरे टूर्नामेंट में उनके शानदार गोल स्कोरिंग प्रदर्शन के सम्मान में दोनों खिलाड़ियों को फुटबॉल बूट्स भेंट किए गए। ओरिएंटल कप 2026 का चौथा संस्करण एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि का गवाह बना, जब टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत की गई।

हॉकी इंडिया देशभर में लगाएगा कोचिंग और ऑफिशिएटिंग एजुकेशन कार्यशालाएं

नई दिल्ली। हॉकी इंडिया ने देशभर में कोचों और तकनीकी अधिकारियों के कौशल विकास के लिए 18 जुलाई से कोचिंग एवं ऑफिशिएटिंग एजुकेशन पाथवे कार्यशालाएं आयोजित करने की घोषणा की है। इनका उद्देश्य आधुनिक कोचिंग तकनीकों, तकनीकी ज्ञान और अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऑफिशिएटिंग मानकों से प्रतिभागियों को परिचित कराना है। हॉकी इंडिया के अनुसार कोचों और तकनीकी अधिकारियों के लिए अलग-अलग कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इन सत्रों का संचालन अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) के शिक्षकों और विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य देशभर में योग्य कोचों और तकनीकी अधिकारियों का मजबूत नेटवर्क तैयार करना है, ताकि खिलाड़ियों के साथ-साथ कोचों और अधिकारियों को भी उच्च गुणवत्ता वाली हॉकी शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। हॉकी इंडिया का मानना है कि खेल के समग्र विकास के लिए खिलाड़ियों के साथ-साथ प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों का लगातार प्रशिक्षण भी बेहद जरूरी है। इसी सोच के तहत यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिससे देशभर में हॉकी शिक्षा को अधिक व्यवस्थित और सुलभ बनाया जा सके।

पिता के त्याग ने मेरे सपनों को दी उड़ान : सोनम उत्तम मस्कर

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाज सोनम उत्तम मस्कर अब 2026 एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे उनके पिता के बड़े त्याग और परिवार के संघर्ष की कहानी छिपी है। 23 वर्षीय सोनम सितंबर में जापान के आइची-नागोया में होने वाले 20वें एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजी टीम का हिस्सा होंगी। शूटिंग प्रतियोगिताएं 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित होंगी। सोनम ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि कोविड-19 महामारी के बाद उनका परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इसी दौरान उन्हें पेशेवर शूटिंग उपकरण की जरूरत थी, लेकिन उसकी कीमत परिवार के लिए बड़ी चुनौती थी। तब उनके पिता उत्तम मारुति मस्कर ने अपनी बेटी का सपना पूरा करने के लिए अपनी एक संपत्ति बेच दी। सोनम ने कहा,एक समय ऐसा था जब हमारा परिवार आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा था, खासकर लॉकडाउन के दौरान। जब यह साफ हो गया कि आगे बढ़ने के लिए मुझे अपना शूटिंग उपकरण चाहिए, तब मेरे पिता ने एक संपत्ति बेच दी ताकि हम वह खरीद सकें। यह हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया।

यूपी टी20 लीग 2026 की शुरुआत 14 अगस्त से, लखनऊ में आगाज, कानपुर में फाइनल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सबसे लोकप्रिय घरेलू टी20 प्रतियोगिता यूपी टी20 लीग 2026 का चौथा सीजन 14 अगस्त से शुरू होगा। उद्घाटन मुकाबले में काशी रुद्रास की टीम का सामना मौजूदा चैंपियन मेरठ मावेरिक्स से भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ में होगा। इस बार टूर्नामेंट 14 अगस्त से 6 सितंबर तक खेला जाएगा। कुल 34 मुकाबले होंगे, जिनमें 13 डबल हेडर और 8 सिंगल हेडर मैच शामिल हैं। पहली बार टूर्नामेंट का आयोजन दो शहरों लखनऊ और कानपुर में किया जाएगा। टूर्नामेंट के पहले चरण में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 13 मैच दिवसों में 22 मुकाबले खेले जाएंगे। इसके बाद प्रतियोगिता का दूसरा चरण कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में होगा, जहां शेष 12 मुकाबले, प्लेऑफ और फाइनल आयोजित किए जाएंगे। यूपी टी20 लीग की संचालन परिषद के अध्यक्ष डॉ. संजय कपूर ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि लीग हर सीजन के साथ नई ऊंचाइयों को छू रही है और इस बार दो शहरों में आयोजन होना टूर्नामेंट के लिए एक बड़ा कदम है।

आईएसएसएफ विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे 'गन फॉर ग्लोरी' के चार निशानेबाज

एजेंसी

नई दिल्ली। गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन (गन फॉर ग्लोरी) के चार निशानेबाज आगामी आईएसएसएफ विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। चीन के हांगझोउ में 20 से 29 जुलाई तक होने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ अपनी चुनौती पेश करेंगे। फाउंडेशन की ओर से ओलंपियन एलावेनिल वलारिवन और रुद्रांक्ष बालासाहेब पाटिल टीम की अगुवाई करेंगे। एलावेनिल महिला 10 मीटर एयर राइफल और 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में हिस्सा लेंगी, जबकि रुद्रांक्ष पुरुष 10 मीटर एयर राइफल और 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगे। इनके अलावा फाउंडेशन की उभरती हुई निशानेबाज साक्षी सुनील पडेकर

(महिला 10 मीटर एयर राइफल) और शाहू तुषार माने (पुरुष 10 मीटर एयर राइफल) भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं। दोनों खिलाड़ी घरेलू प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन और अकादमी में लंबे समय तक की गई तैयारी के बाद विश्व कप में उतरेंगे। पिछले तीन वर्षों से गन फॉर ग्लोरी अकादमी से जुड़ी साक्षी सुनील पडेकर ने हाल के दिनों में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। विश्व कप से पहले उन्होंने फाउंडेशन की ओर से जारी एक बयान में कहा, मेरा पूरा ध्यान एक समय में एक शॉट पर रहेगा। यही सोच अब तक मेरे लिए कारगर रही है। पिछले कुछ सप्ताह में हमने तकनीकी पहलुओं पर काफी काम किया है और मुझे अपनी तैयारी तथा अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है। हर प्रतियोगिता सीखने का अवसर होती है और मैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ खुद को परखने के लिए उत्साहित हूं। पुरुष वर्ग के निशानेबाज शाहू तुषार माने भी पिछले ढाई वर्षों से गन फॉर ग्लोरी अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। हाल ही में एयर राइफल ट्रायल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले शाहू ने कहा कि उनका लक्ष्य केवल अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर ध्यान देना है। उन्होंने कहा, मैं विश्व कप में किसी विशेष लक्ष्य के साथ नहीं जा रहा हूं। जब मैंने हाल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, तब मैं केवल खेल का आनंद ले रहा था और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। इस बार भी मैं उसी सोच के साथ उतरूंगा। यदि मैं अपनी दिनचर्या का पालन करूं और हर पल का आनंद लेते हुए निशाना लगाऊं, तो परिणाम अपने आप मिल जाएंगे।

आईसीसी आचार संहिता उल्लंघन के लिए गुरनूर बरार को मिली चेतावनी

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत के तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में 14 जुलाई को खेले गए पहले एकदिवसीय मैच के दौरान आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने उन्हें लेवल-1 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए आधिकारिक चेतावनी जारी की है। आईसीसी के कहा कि गुरनूर बरार ने खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ के लिए निर्धारित आचार संहिता के अनुच्छेद 2.9 का उल्लंघन किया, जो अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान किसी खिलाड़ी की ओर अनुचित या खतरनाक तरीके से गेंद फेंकने से संबंधित है। इसके अलावा बरार के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा गया है। पिछले 24 महीनों में यह उनका पहला उल्लंघन है।यह घटना इंग्लैंड की पारी के आठवें ओवर में हुई। फील्डिंग के दौरान गुरनूर बरार ने गेंद उठाकर बल्लेबाज की दिशा में अनुचित और खतरनाक तरीके से फेंक दी थी। मैदान पर मौजूद अंपायर कुमार धर्मसेना और माइक बर्न्स, तीसरे अंपायर सैम नोगाजस्की तथा चौथे अंपायर रसेल वॉरेन ने बरार के खिलाफ आरोप लगाया था। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन (एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल) की ओर से प्रस्तावित सजा को बरार ने स्वीकार कर लिया और अपना दोष भी मान लिया। इसके चलते औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। आईसीसी के नियमों के अनुसार लेवल-1 के उल्लंघन पर न्यूनतम सजा आधिकारिक फटकार होती है।

एनआरएआई और बाल्मर लॉरी के बीच समझौता, निशानेबाजों के लिए शुरू होगा विशेष ट्रैवल पोर्टल

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) ने अपने खिलाड़ियों, अधिकारियों और सदस्यों की घरेलू यात्रा को आसान और किफायती बनाने के लिए बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) किया है। इस पहल के तहत देश के लगभग 80 हजार पंजीकृत निशानेबाजों के लिए एक विशेष डिजिटल सेल्फ बुकिंग ट्रैवल पोर्टल शुरू किया जाएगा। यह पहली बार है जब किसी भारतीय खेल महासंघ ने अपने सदस्यों के लिए समर्पित कॉर्पोरेट ट्रैवल सिस्टम विकसित किया है। इस पोर्टल के माध्यम से खिलाड़ी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के साथ-साथ अपनी निजी घरेलू यात्राओं की भी स्वयं बुकिंग कर सकेंगे। एनआरएआई के अध्यक्ष कालिकेश नारायण सिंह देव ने कहा कि लगातार होने वाली प्रतियोगिताओं के दौरान यात्रा की व्यवस्था खिलाड़ियों के लिए अतिरिक्त चुनौती बन जाती है। उन्होंने कहा कि इस नए पोर्टल से खिलाड़ियों का समय और ऊर्जा बचेगी तथा वे पूरी तरह अपने प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। इस पोर्टल पर घरेलू उड़ानों के लिए कॉर्पोरेट रियायती किराया,

निःशुल्क भोजन, पसंदीदा सीट चयन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। खास बात यह है कि यही लाभ खिलाड़ियों की व्यक्तिगत यात्रा पर भी उपलब्ध होंगे। परिवार की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पोर्टल में डिपेंडेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी जोड़ा गया है, जिसके तहत एक खिलाड़ी अपने छह तक पारिवारिक सदस्यों को जोड़ सकेगा। इसके अलावा टिकट बुकिंग पर कोई सर्विस शुल्क नहीं लिया जाएगा और केवल पेमेंट गेटवे शुल्क लागू होगा। टिकट रद्द कराने पर भी एयरलाइन की नीति के अनुरूप न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। एनआरएआई के महासचिव पवन कुमार सिंह ने कहा कि महासंघ खिलाड़ियों के लिए अधिक सुविधाजनक और सहयोगी व्यवस्था तैयार करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। उनके अनुसार यह ट्रैवल पोर्टल खिलाड़ियों और अधिकारियों की यात्रा को सरल, किफायती और व्यवस्थित बनाएगा।

पीवी सिंधु जापान ओपन के सेमीफाइनल में, अब चीन की चेन यूफेई से होगी टक्कर

एजेंसी

टोक्यो। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पी. वी. सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में उनकी प्रतिद्वंद्वी और मेजबान जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा चोट के कारण मुकाबले से हट गईं, जिसके चलते सिंधु को वॉकओवर मिल गया। इस जीत के साथ सिंधु ने वर्ष 2023 के डेनमार्क ओपन के बाद पहली बार किसी सुपर 750 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। साथ ही यह वर्ष 2026 में उनका तीसरा सेमीफाइनल भी है, जो इस सीजन में उनकी शानदार वापसी को दर्शाता है। सत्र की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से करने वाली सिंधु अब शीर्ष-10 में वापसी कर चुकी हैं और वर्तमान में विश्व नंबर-9 हैं।

सेमीफाइनल में चेन यूफेई से होगी चुनौती

सेमीफाइनल में सिंधु का सामना चीन की पूर्व ओलंपिक चैंपियन और विश्व नंबर-4 चेन यूफेई से होगा। चेन ने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सिम यू जिन को 21-

10, 21-12 से हराकर अंतिम चार में प्रवेश किया। सिंधु और चेन के बीच अब तक 14 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें चीनी खिलाड़ी 8-6 से आगे हैं। खास बात यह है कि सिंधु पिछले पांच मुकाबलों में लगातार चेन से हार चुकी हैं।

ऐसे में सेमीफाइनल मुकाबला सिंधु के लिए बड़ी चुनौती होगा। यदि वह इस मुकाबले में जीत दर्ज करती हैं तो न केवल चेन के खिलाफ अपनी हार का सिलसिला समाप्त करेंगी, बल्कि लगभग तीन वर्षों बाद किसी सुपर 750 टूर्नामेंट के फाइनल में भी जगह बना लेंगी।

महिला हॉकी विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम घोषित, सलीमा टेटे को सौंपी गई कप्तानी

एजेंसी

नई दिल्ली। हॉकी इंडिया ने शुक्रवार को बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित होने वाले एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप 2026 के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। अनुभवी मिडफील्डर सलीमा टेटे को टीम की कप्तानी सौंपी गई है। मुख्य कोच सजॉर्ड मारिजन ने चयनित टीम को अनुभव और युवा खिलाड़ियों का संतुलित मिश्रण बताया है।

महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन 15 से 30 अगस्त 2026 तक बेल्जियम और नीदरलैंड की संयुक्त मेजबानी में होगा। भारतीय टीम फिलहाल बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय शिविर में तैयारियों में जुटी हुई है। भारतीय टीम ने पिछले महीने न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच नेशंस कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपराजित रहते हुए खिताब जीता था। विश्व कप के लिए चुनी गई टीम में उसी प्रदर्शन से प्रभावित कई खिलाड़ियों को जगह दी गई है।

पूल-डी में भारत की चुनौती

विश्व कप में भारत को पूल-डी

में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ रखा गया है। भारतीय टीम अपने सभी ग्रुप मुकाबले नीदरलैंड के एम्स्टेलवीन स्थित वागेनर हॉकी स्टेडियम में खेलेगी। भारत अपने अभियान की शुरुआत 16 अगस्त को चीन के खिलाफ करेगा। इसके बाद 18 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका और 20 अगस्त को इंग्लैंड से मुकाबला होगा। मुख्य कोच सजॉर्ड मारिजन ने कहा, हमने ऐसी संतुलित टीम का चयन किया है जो इस गर्मी में मिलने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार है। खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट से पहले कड़ी मेहनत की है और हमें उनकी क्षमता पर पूरा भरोसा है। हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ खेलते हुए सबसे बड़े मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं।

भारतीय टीम

गोलकीपरः सविता, बिचू देवी खरीबाम

डिफेंडरः इशिका चौधरी, सुशीला चानू पुखरामबम, लालथांतलुआंगी, ज्योति, शिल्पी डबास

मिडफील्डरः सलीमा टेटे (कप्तान), निक्की प्रधान, साक्षी राणा, सुनेलिता टोप्पो, नेहा, दीपिका सोरेंग

फॉरवर्डः लालरेमसियामी, रुतुजा दादासो पिसाल, नवनीत कौर, दीपिका, इशिका, बलजीत कौर, ब्यूटी डुंगडुंग।

लुइस सुआरेज़ ने रोनाल्डो नाज़ारियो को बताया 'सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ नंबर-9', साझा की तस्वीर

एजेंसी

मोंटेवीडियो (उरुग्वे)। उरुग्वे के स्टार फुटबॉलर लुइस सुआरेज़ ने ब्राजील के महान फुटबॉलर रोनाल्डो नाज़ारियो के साथ मुलाकात के बाद भावुक पोस्ट साझा करते हुए उन्हें सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ नंबर-9 बताया है। सुआरेज़ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर रोनाल्डो नाज़ारियो के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की। इसके साथ उन्होंने लिखा, सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ नंबर-9! रोनाल्डो नाज़ारियो को फुटबॉल इतिहास के महानतम स्ट्राइकरों में गिना जाता है। उन्होंने ब्राजील को विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी और अपने शानदार करियर के दौरान कई व्यक्तिगत और टीम सम्मान हासिल किए।

हैरी केन के साथ भी साझा की थी खास तस्वीर

इससे पहले फीफा विश्व कप 2026 के दौरान इंटर मियामी के स्ट्राइकर लुइस सुआरेज़ ने इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन के साथ भी एक खास पल साझा किया था। सुआरेज़ ने एक्स पर दोनों खिलाड़ियों की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा था,

एक शानदार नंबर-9 के साथ! आपसे मिलकर खुशी हुई। तस्वीर में सुआरेज़ और केन एक-दूसरे की नंबर-9 जर्सी थामे नजर आए। दोनों दिग्गज स्ट्राइकरों ने गर्मजोशी से मुलाकात की और आपस में जर्सी का आदान-प्रदान किया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी पसंद की गई।

फीफा विश्व कप से बाहर होने के बाद बेलिंघम का भावुक संदेश, बोले- एकजुट रहेंगे तो बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे

एजेंसी

नई दिल्ली। फीफा विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से हारकर टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद इंग्लैंड के स्टार फुटबॉलर जूड बेलिंघम ने प्रशंसकों के नाम भावुक संदेश साझा किया है। उन्होंने टीम को पूरे टूर्नामेंट में मिले शानदार समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए देशवासियों से एकजुटता बनाए रखने की अपील की। रियल मैड्रिड के मिडफील्डर बेलिंघम ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर लिखा कि सेमीफाइनल में मिली हार के बाद उन्हें अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन प्रशंसकों का प्यार और समर्थन उनके लिए बेहद खास रहा।

प्रशंसकों को कहा धन्यवाद

बेलिंघम ने अपने संदेश में लिखा, कल और पिछले कुछ हफ्तों

को लेकर सही शब्द ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन हमारे ड्राइवर ने जो कहा, उसने मेरी भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त कर दिया। इंग्लैंड में मौजूद सभी लोगों और उन प्रशंसकों का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई खर्च कर अमेरिका आकर हमारा समर्थन किया। उन्होंने आगे कहा, इस अभियान के साथ हमारे देश में दिखाई दी एकजुटता और प्यार खत्म नहीं होना चाहिए। जब हम साथ होते हैं तो बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं... और हम जरूर करेंगे। आप सभी से प्यार।

सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने छीनी जीत

इंग्लैंड का विश्व कप अभियान सेमीफाइनल में गत चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ 2-1 की हार के साथ समाप्त हुआ। इंग्लैंड ने मुकाबले में शुरुआती बढ़त बनाई थी, लेकिन अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडीज ने बराबरी का गोल दाग दिया। इसके बाद अतिरिक्त समय (स्टॉपेज टाइम) में लौतारो मार्टिनेज ने विजयी गोल कर अर्जेंटीना को फाइनल में पहुंचा दिया, जबकि इंग्लैंड का विश्व कप जीतने का सपना एक बार फिर अधूरा रह गया। बेलिंघम के संदेश को सोशल मीडिया पर प्रशंसकों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। इंग्लैंड के इस युवा स्टार ने विश्वास जताया कि यदि टीम और प्रशंसक इसी तरह एकजुट रहे, तो भविष्य में इंग्लैंड बड़ी सफलताएं हासिल करेगा।

कोहली और गंभीर के बीच किसी 'ब्रिज' की जरूरत नहीं : सितांशु कोटक

एजेंसी

कार्डिफ (यूके)। भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने मुख्य कोच गौतम गंभीर और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के बीच मतभेदों की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि दोनों के बीच नियमित बातचीत होती है और उन्हें किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय मैच में भारत की चार विकेट से हार के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोटक ने स्पष्ट किया कि अभ्यास सत्र के दौरान विराट कोहली से उनकी बातचीत केवल बल्लेबाजी से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच संवाद का माध्यम बने हुए हैं, तो कोटक ने कहा, नहीं, विराट और गौतम आज ही शायद 10-12 बार बात कर चुके होंगे। मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी ब्रिज की जरूरत है।

बल्लेबाजी पर हुई थी चर्चा

कोटक ने बताया कि विराट ने खुद बल्लेबाजी से जुड़े कुछ पहलुओं पर उनसे चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि इतने अनुभवी बल्लेबाज को बिना जरूरत तकनीकी सलाह देना उचित नहीं होता। उन्होंने कहा, विराट बल्लेबाजी के लिए जाने से पहले कुछ चीजों पर बात करना चाहते थे। ईमानदारी से कहूं तो जब तक उन्हें खुद किसी बात की जरूरत महसूस न हो या कोई बड़ी तकनीकी बात नजर न आए, तब तक उनकी बल्लेबाजी में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। उन्होंने फुटवर्क और कुछ अन्य पहलुओं को लेकर मुझसे चर्चा की थी और नेट्स के बाद भी इसी विषय पर बात हुई।

अफवाहों को बताया निराधार

कोटक ने कोहली और गंभीर के रिश्तों को लेकर चल रही चर्चाओं को भी सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा, इन अफवाहों की बात करें तो मुझे नहीं पता कि ये कहां से आती हैं, लेकिन आती जरूर हैं।

ल्यूक रोंची छोड़ेंगे न्यूजीलैंड टीम के बैटिंग कोच का पद, बीबीएल में मेलबर्न रेनेगेड्स से जुड़ेंगे

एजेंसी

क्राइस्टचर्च । ल्यूक रोंची न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच के पद से इस्तीफा देंगे। वह बिग बैश लीग (बीबीएल) में मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम के नए हेड कोच बनेंगे। रोंची अक्टूबर में न्यूजीलैंड के भारत दौरे के दौरान टीम के साथ काम करना जारी रखेंगे और सीरीज खत्म होने के बाद मेलबर्न रेनेगेड्स से जुड़ेंगे। रोंची ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, दोनों देशों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। उन्होंने साल 2020 में न्यूजीलैंड टीम के फुल-टाइम बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी संभाली थी। उस समय पीटर फुल्टन के कैंटरबरी का मुख्य कोच बनने के बाद यह पद खाली हुआ था। रोंची ने कहा कि नेशनल टीम के साथ काम करना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा रहा। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों तक खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के साथ काम करने का मौका मिलना उनके लिए गर्व की बात है। उनका हमेशा यही लक्ष्य रहा कि टीम के बल्लेबाज इंटरनेशनल स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि इस दौरान टीम के साथ कई यादगार पल बिताने का अवसर मिला, जिन्हें वह हमेशा याद रखेंगे। रोंची के कार्यकाल में न्यूजीलैंड टीम ने कई बड़ी सफलताएं हासिल कीं। टीम ने 2021 में पहली बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता।

रूट की बेहतरीन पारी की बदौलत इंग्लैंड ने भारत को चार विकेट से हराकर वनडे सीरीज 1-1 से की बराबर

कार्डिफ। जो रूट की जिम्मेदारी भरी नाबाद 99 रन की पारी के दम पर इंग्लैंड ने दूसरे एकदिवसीय मुकाबले में भारत को चार विकेट से हरा दिया। सोफिया गार्डन्स में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने 234 रन के लक्ष्य को 44.1 ओवर में छह विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई और अब रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाने वाला तीसरा वनडे निर्णायक मुकाबला होगा। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने भारत को 44 ओवर में 233 रन पर समेट दिया। भारत की ओर से विराट कोहली ने 65 और श्रेयस अय्यर ने 66 रन बनाए। इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। कप्तान शुभमन गिल ने 31, रोहित शर्मा ने 26 और जसप्रीत बुमराह ने नाबाद 20 रन का योगदान दिया। इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट झटके। गस एटकिंसन ने भी तीन विकेट हासिल किए, जबकि साकिब महमूद को दो सफलता मिली।

रूट ने संभाली इंग्लैंड की लड़खड़ाती पारी

234 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। बेन डकेट, जैकब बेथेल और कप्तान हैरी ब्रूक सस्ते में आउट हो गए, जिससे टीम 53 रन पर तीन विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद अनुभवी जो रूट ने एक छोर संभाले रखा और संयम के साथ पारी को आगे बढ़ाया। रूट को सैम करन (26), विल जैक्स (30) और अंत में गस एटकिंसन (नाबाद 23) का अच्छा साथ मिला। रूट अपने शतक से सिर्फ एक रन दूर रह गए, लेकिन उनकी नाबाद 99 रन की पारी ने इंग्लैंड को 35 गेंद शेष रहते जीत दिला दी। यह उनके वनडे करियर का लगातार पांचवां 50 से अधिक का स्कोर भी रहा।

भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में बनाया दबाव

भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पहली ही गेंद पर विकेट लेकर इंग्लैंड पर दबाव बना दिया। प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार ने भी शुरुआती सफलता दिलाई, लेकिन मध्यक्रम में रूट की सूझबूझ भरी बल्लेबाजी के सामने भारतीय गेंदबाज मैच पर पकड़ बनाए नहीं रख सके। गुरनूर बरार ने दो विकेट लिए, जबकि अन्य गेंदबाज नियमित अंतराल पर विकेट लेने में सफल नहीं रहे।

कोहली और अय्यर ने संभाली थी भारतीय पारी

भारत की पारी की शुरुआत भी खास नहीं रही, लेकिन विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने चौथे विकेट के लिए 67 रन जोड़कर टीम को संभाला। कोहली ने सात चौकों की मदद से 65 रन बनाए, जबकि अय्यर ने 66 रन की जुझारू पारी खेली। हालांकि, आर्चर ने लगातार झटके देकर भारत की पारी को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया।

अंतिम ओवरों में बुमराह ने कुछ आक्रामक शॉट लगाए, लेकिन भारत 233 रन से आगे नहीं बढ़ सका।

संक्षिप्त स्कोर

भारतः 233 ऑल आउट (44 ओवर), श्रेयस अय्यर 66, विराट कोहली 65, शुभमन गिल 31, रोहित शर्मा 26, जसप्रीत बुमराह नाबाद 20।

गेंदबाजी (इंग्लैंड): जोफ्रा आर्चर 3/47, गस एटकिंसन 3/50, साकिब महमूद 2 विकेट।

इंग्लैंडः 235/6 (44.1 ओवर)

जो रूट नाबाद 99, विल जैक्स 30, सैम करन 26, गस एटकिंसन नाबाद 23।

गेंदबाजी (भारत): गुरनूर बरार 2 विकेट।

परिणामः इंग्लैंड ने चार विकेट से जीत दर्ज की। सीरीज 1-1 से बराबर। अब निर्णायक तीसरा वनडे रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा।

'पैमाना' डैशबोर्ड की त्रैमासिक रिपोर्ट दर्शाती है बुनियादी ढांचागत क्षेत्र की तेज प्रगति

मुंबई। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की उपलब्धियों पर दृष्टि रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित डैशबोर्ड 'पैमाना' की त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार विमान, रेलवे, राजमार्ग, दूरसंचार और पोत परिवहन जैसे बुनियादी क्षेत्रों ने हाल के वर्षों में अच्छी प्रगति दर्ज की गयी है। पैमाना की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2026 में विमानों के जरिए माल ढुलाई 98,920.10 टन रही, जो अप्रैल 2025 की तुलना में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा गुरुवार को जारी पैमाना (राष्ट्र निर्माण के लिए परियोजना मूल्यांकन, आधारभूत ढांचा निगरानी एवं विश्लेषण) डैशबोर्ड की अद्यतन त्रैमासिक रिपोर्ट में विमानन, रेलवे , पोत परिवहन, राजमार्ग और दूरसंचार जैसे बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के प्रदर्शन की निगरानी की जाती है। इसी वर्ष 16 अप्रैल को शुरू किये गये इस डैशबोर्ड की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार अनुसार देश में हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर 165 हो गयह है, जो 2014 में 81 थी। रिपोर्ट के मुताबिक दूरसंचार क्षेत्र में डिजिटल क्षेत्र में मजबूत वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान वायरलेस-मोबाइल डेटा की खपत 2,85,376 पेटाबाइट्स (पीबी) तक पहुंच गयी, जो इससे पिछले वर्ष की तुलना में 24.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस दौरान टेलीफोन ग्राहकों (कनेक्शनों) की संख्या 10.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 133.06 करोड़ हो गयी जो एक साल पहले 120.17 करोड़ थी।

टेक महिंद्रा का मुनाफा पहली तिमाही में बढ़कर 1,465 करोड़ रुपये हुआ

मुंबई। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी टेक महिंद्रा का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 28.4 प्रतिशत बढ़कर 1,465 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। आलोच्य तिमाही में कंपनी का कुल राजस्व 17.7 फीसदी की वृद्धि के साथ 15,712 करोड़ रुपये रहा। परिचालन लाभ सालाना आधार पर 53.3 प्रतिशत बढ़ा और 2,264 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी ने बताया कि तिमाही के दौरान उसके कर्मचारियों की संख्या घटकर 30 जून 2026 को 1,46,760 रह गयी। यह तीन महीने पहले की तुलना में 863 कर्मचारी कम है। तिमाही के अंत में कंपनी के पास 9,695 करोड़ रुपये की नकदी थी। टेक महिंद्रा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक मोहित जोशी ने कहा कि यह लगातार तीसरी तिमाही है जिसमें कंपनी ने एक अरब डॉलर से अधिक के अनुबंध हासिल किये। यह कंपनी की कारोबारी मजबूती और उसके उत्पादों की प्रासंगिकता दिखाता है। पांच करोड़ डॉलर से अधिक के क्लाइंट की संख्या में सात का इजाफा हुआ।

विप्रो को पहली तिमाही में 3,356 करोड़ रुपये का मुनाफा

बेंगलुरु। देश की अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में समेकित आधार पर 3,356 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। यह पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के 3,337 करोड़ रुपये के मुकाबले 0.6 प्रतिशत अधिक है। वहीं, तिमाही-दर-तिमाही इसमें 4.7 प्रतिशत की गिरावट आयी है। कंपनी के निदेशकमंडल की यहां गुरुवार को हुई बैठक में वित्तीय परिणामों को मंजूरी प्रदान की गयी। निदेशकमंडल ने दो रुपये के अंकित मूल्य वाले हर इक्विटी शेयर पर दो रुपये का अंतरिम लाभांश देने का प्रस्ताव किया है। अंतरिम लाभांश के आवंटन के लिए 27 जुलाई की शेयरधारिता को आधार बनाया जायेगा। लाभांश का भुगतान 14 अगस्त को किया जायेगा। तिमाही के दौरान कंपनी का परिचालन राजस्व 10.59 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 24,477 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यह एक साल पहले 22,135 करोड़ रुपये रहा था। अप्रैल-जून 2026 की तिमाही में आईटी सेवा सेग्मेंट से प्राप्त राजस्व तिमाही आधार पर 1.4 प्रतिशत घटकर 261.45 करोड़ डॉलर रह गया। कंपनी ने बताया है कि आने वाले तिमाही में आईटी सेवा कारोबार से प्राप्त राजस्व 2.57 अरब डॉलर से 2.63 अरब डॉलर के बीच रहने की उम्मीद है। विप्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंधन निदेशक स्रीनि पल्लिया ने परिणामों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि क्लाइंट अब टेक्नोलॉजी के आधुनिकीकरण से आगे एआई आधारित परिचालन मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं जो गुणवत्ता, मजबूती और उत्पादकता बढ़ाने में मददगार होंगे।

सेंसेक्स शुरुआती तेजी के बाद सपाट बंद हुआ

मुंबई। विदेशों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को बिकवाली हावी रही, हालांकि आईटी और ऑटो सेक्टरों में लिवाली से प्रमुख सूचकांक लगभग सपाट बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स 203 अंक की मजबूती के साथ खुलने के बाद दोपहर तक बढ़त में बना रहा। दोपहर बाद बिकवाली का दबाव बढ़ने से सूचकांक अंत में मात्र 1.44 अंक ऊपर 77,186.87 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी दोपहर तक हरे निशान में रहने के बाद बिकवाली के दबाव में 5.75 प्रतिशत यानी 0.02 फीसदी टूटकर 24,072.75 अंक पर आ गया। वृहत बाजार में बिकवाली देखी गयी। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.29 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.10 प्रतिशत नीचे बंद हुआ। टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद, रसायन, आईटी, ऑटो, मीडिया और एफएमसीजी सेक्टर हरे निशान में रहे। वित्तीय, बैंकिंग, रियल्टी और धातु सेक्टरों में गिरावट रही। सेंसेक्स की कंपनियों में इंडिगो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, टाइटन और आईटीसी के शेयरों में एक से दो प्रतिशत की तेजी रही। टीसीएस और इंफोसिस के शेयर भी बढ़त में रहे।

भारत और फिनलैंड यूरोपीय संघ के एफटीए के तहत अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए तैयार हैं: पीयूष गोयल

एजेंसी

नई दिल्ली । केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फिनलैंड की उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रिक्का पुर्रा से मुलाकात कर दोनों देशों के बीच आर्थिक और वित्तीय सहयोग को मजबूत बनाने, व्यापार और निवेश बढ़ाने तथा डिजिटलीकरण और उभरते क्षेत्रों में साझेदारी का विस्तार करने पर चर्चा की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) के तहत भारत और फिनलैंड के बीच सहयोग को और गहरा करने की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया। पीयूष गोयल बेल्जियम और स्पेन की सफल यात्रा के बाद फिनलैंड पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने फिनलैंड के आर्थिक मामलों के मंत्री साकारी पुइस्तो के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक की। गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश,

इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी), स्टार्टअप और बिजनेस पार्टनरशिप को मजबूत बनाने के उपायों पर सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), 6जी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमिकंडक्टर, स्पेस और सस्टेनेबिलिटी जैसे भविष्य के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार किया गया। साथ ही इस बात पर भी चर्चा हुई कि भारत-ईयू एफटीए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को किस तरह नई गति दे सकता है। फिनलैंड यात्रा का मुख्य उद्देश्य इनोवेशन, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल रिसर्च जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान पीयूष गोयल फिनलैंड की प्रमुख कंपनियों के साथ आयोजित इंडिया-फिनलैंड बिजनेस राउंडटेबल में भी हिस्सा लेने वाले हैं। इस बैठक में डिजिटलीकरण, क्लीन एनर्जी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और सर्कुलर इकोनॉमी से जुड़ी फिनलैंड की कंपनियां शामिल होंगी। इसके अलावा, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और बिजनेस फिनलैंड के बीच संस्थागत सहयोग को मजबूत बनाने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। पीयूष गोयल फिनलैंड की कई प्रमुख कंपनियों और इनोवेशन संस्थानों, जिनमें नोकिया कॉरपोरेशन, वीटीटी रिसर्च सेंटर, कोने कॉरपोरेशन और केम्पी ग्रुप शामिल हैं, का भी दौरा करेंगे। इस दौरान टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, 6जी रिसर्च, स्मार्ट मोबिलिटी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल मोबिलिटी, इंडस्ट्रियल इनोवेशन और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा होगी।

रुपया 17 पैसे टूटा, आठ सप्ताह के निचले स्तर पर

एजेंसी

मुंबई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल में तेजी से डॉलर की तुलना में रुपये में गिरावट रही और यह आठ सप्ताह के निचले स्तर पर आ गया। कच्चे तेल का मानक लंदन का ब्रेंट क्रूड वायदा आज आधा फीसदी से अधिक चढ़कर 85 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया। साथ ही दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर सूचकांक भी 0.1 प्रतिशत से ज्यादा मजबूत हुआ। इन दोनों कारकों ने भारतीय मुद्रा पर दबाव बनाया। अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में सुबह कुछ देर के लिए बढ़त में रहने के बाद रुपये पर दबाव देखा गया। अंतिम समय में बिकवाली बढ़ने से यह 17 पैसे की गिरावट में 96.42 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। यह इस साल 20 मई के बाद का इसका निचला स्तर है। पिछले कारोबारी दिवस पर भारतीय मुद्रा नौ पैसे टूटकर 96.25 रुपये

प्रति डॉलर पर बंद हुई थी। रुपये की शुरुआत तीन पैसे की गिरावट में 96.28 रुपये प्रति डॉलर पर हुई थी। बीच कारोबार में यह ऊपर 96.22 रुपये और नीचे 96.42 रुपये प्रति डॉलर तक गया। अंत में 96.42 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

पिछले एक वर्ष में आईसीएआर ने की 44 फसलों की 386 उन्नत किस्में

एजेंसी

नई दिल्ली। केन्द्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद(आईसीएआर) के वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचारों ने देश में खाद्यान्न, बागवानी, दुग्ध एवं मत्स्य उत्पादन में रिकॉर्ड उपलब्धियां हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष में आईसीएआर ने 44 फसलों की 386 उन्नत किस्में विकसित की हैं, जिनमें से 94 प्रतिशत जलवायु-अनुकूल हैं तथा 29 जैव-सुदृढ़ीकृत (बायोफोर्टिफाइड) किस्में हैं। उन्होंने मांग-आधारित अनुसंधान, जलवायु-अनुकूल कृषि, दलहन एवं तिलहन में आत्मनिर्भरता, गुणवत्तापूर्ण कृषि शिक्षा, प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण तथा कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) नेटवर्क के माध्यम से नवाचारों के व्यापक प्रसार की आवश्यकता पर जोर दिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के 98वां स्थापना दिवस के मौके पर अपने संबोधन में केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 98 वर्षों में आईसीएआर ने भारत की कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने, उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आजीविका में सुधार करने तथा देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, तथा कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, नीति आयोग के सदस्य के.वी. राजू तथा मत्स्य पालन विभाग के सचिव नरेश पाल गंगवार भी उपस्थित थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) नेटवर्क के माध्यम से अनुसंधान की पहुंच का विस्तार करने का आह्वान किया ताकि प्रयोगशालाओं से किसानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों तक प्रौद्योगिकियों का तेजी से हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा आईसीएआर के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) से अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी प्रसार को और मजबूती मिलेगी, जिससे किसानों की समृद्धि तेज होगी और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायता मिलेगी।

सरकार ने डीजल और एटीएफ के निर्यात पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स, पेट्रोल पर की कटौती

एजेंसी

नई दिल्ली।केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स को बढ़ा दिया है। वहीं, पेट्रोल पर कटौती की है। इसकी वजह अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आना था। नई दरें गुरुवार से लागू हो गई हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि डीजल पर निर्यात शुल्क बढ़कर 15.5 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जो कि पहले 8.5 रुपए प्रति लीटर था। एटीएफ पर निर्यात शुल्क 7.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 14.5 रुपए प्रति लीटर हो गया। इसके अलावा, सरकार ने पेट्रोल पर निर्यात शुल्क को 4 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 2.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया है।

यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आया है और बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 85 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है। मध्य पूर्व में

तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सभी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी फिर से लागू कर दी है, जिसके जवाब में ईरान ने इलाके में अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जवाबी हमले किए। इस महीने की शुरुआत में, सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बदलाव किया था। इसके तहत पेट्रोल पर निर्यात शुल्क बढ़ाया गया, जबकि डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर निर्यात शुल्क में कटौती की गई। इस दौरान पेट्रोल निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (एसएईडी) को 1.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 4 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया। साथ ही, डीजल पर निर्यात शुल्क को 14 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 8.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया, जबकि एटीएफ पर निर्यात शुल्क को 12.5 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 7.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया।

सरकार घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के एक्सपोर्ट पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स की समय-समय पर समीक्षा करती है ताकि शुल्क को अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और रिफाइनिंग मार्जिन में होने वाले बदलावों के हिसाब से समायोजित किया जा सके।

पीएम मोदी की उड़ान योजना से दमन को मिली दिल्ली के लिए पहली सीधी उड़ान, पर्यटन और कारोबार को मिलेगा बड़ा बढ़ावा: राम मोहन नायडू

एजेंसी

नई दिल्ली । केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के तहत दमन को पहली बार दिल्ली के लिए सीधी हवाई सेवा मिली है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार को नई गति देने वाली साबित होगी। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार, मंत्री ने नवनिर्मित नमो एयरपोर्ट से एलायंस एयर की दमन-दिल्ली-दमन मार्ग पर पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाने के बाद यह बात कही। राम मोहन नायडू ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि इस नई हवाई सेवा के शुरू होने से दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच यात्रा का समय, जो सड़क मार्ग से लगभग 8 से 10 घंटे लगता था, अब घटकर करीब ढाई घंटे रह जाएगा।उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उड़ान योजना को देते हुए कहा कि इस योजना ने देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को पूरी तरह बदल दिया है। इसके माध्यम से छोटे शहरों को देश के

प्रमुख शहरों से जोड़ा जा रहा है, जिससे आम लोगों को तेज, सुलभ और सुविधाजनक हवाई यात्रा का लाभ मिल रहा है। नमो एयरपोर्ट भारतीय तटरक्षक बल के इंडियन कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन (आईसीजीएएस), दमन में विकसित दोहरे उपयोग वाली हवाई सुविधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को इसका उद्घाटन किया था, जबकि इसकी आधारशिला अप्रैल 2023 में रखी गई थी।

करीब 25 एकड़ क्षेत्र में 124 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इस एयरपोर्ट में 3,700 वर्ग मीटर का आधुनिक टर्मिनल बनाया गया है, जो प्रतिदिन 14 एटीआर विमानों के संचालन में सक्षम है और इसकी वार्षिक यात्री क्षमता लगभग 3.67 लाख यात्रियों की है। मंत्री ने कहा कि दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली क्षेत्र औद्योगिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र हैं। यहां 7,000 से अधिक उद्योग संचालित हो रहे हैं, जबकि आसपास के वापी और वलसाड क्षेत्रों में लगभग 15,000 उद्योग मौजूद हैं। ऐसे में बेहतर हवाई संपर्क से कारोबारी यात्राएं आसान होंगी, नए निवेश आकर्षित होंगे और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि हर वर्ष करीब 20 लाख पर्यटक दमन घूमने आते हैं। नई सीधी हवाई सेवा शुरू होने के बाद पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय पर्यटन उद्योग को भी बड़ा लाभ मिलेगा।

सरकार भविष्य में एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार करने की भी योजना बना रही है, ताकि एयरबस ए320 जैसे बड़े विमान भी यहां से उड़ान भर सकें। इसके बाद मुंबई, सूरत, अहमदाबाद और पटना जैसे शहरों के लिए भी सीधी हवाई सेवाएं शुरू करने की तैयारी है।

केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि सरकार ने उड़ान योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। संशोधित योजना के तहत 29,000 करोड़ रुपए के बजट से देश भर में 100 नए एयरपोर्ट और 200 नए हेलीपैड विकसित किए जाएंगे, जिससे क्षेत्रीय हवाई संपर्क को और मजबूत किया जा सकेगा।

जियो फाइनेंस का मुनाफा 156 प्रतिशत बढ़कर 830 करोड़ रुपये हुआ

एजेंसी

मुंबई। रिलायंस समूह की वित्तीय कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 830 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो एक साल पहले की समान तिमाही से 156 प्रतिशत अधिक है। कंपनी के निदेशक मंडल की हुई बैठक में वित्तीय परिणामों को स्वीकृति प्रदान की गयी। आलोच्य तिमाही में कंपनी का परिचालन राजस्व 3.27 गुना होकर 2,004 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। लाभांश को छोड़कर कंपनी की कुल आय 1,496 करोड़ रुपये रही जो सालाना आधार पर 141 प्रतिशत बढ़ी है। लाभांश सहित शुद्ध लाभ 131 फीसदी बढ़कर 970 करोड़ रुपये रहा। जियो फाइनेंस की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कंपनी के प्रवर्तक समूह से पहली तिमाही में 5,934 करोड़ रुपये की दूसरी पूंजी किस्त प्राप्त हुई, जिससे कुल पूंजी निवेश बढ़कर 9,890 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने बताया कि उसके सभी व्यवसायों में तेजी से वृद्धि हुई है। जियो क्रेडिट लिमिटेड के ऋण कारोबार, एसेट मैनेजमेंट और पेमेंट्स व्यवसाय में लगातार विस्तार हुआ है। साथ ही जियोफाइनेंस ऐप पर बढ़ती डिजिटल भागीदारी और मजबूत ट्रेज़री संचालन ने नये संयुक्त उपक्रमों को भी मजबूत आधार प्रदान किया है। जियोफाइनेंस ऐप पर प्रतिदिन औसतन 34 हजार उत्पादों की खरीद दर्ज की गयी। रिवॉर्ड कार्यक्रम के तहत 20.4 करोड़ जियोप्वाइंट्स जारी किये गये और 57 लाख ग्राहक इससे लाभांवित होंगे। जियो क्रेडिट लिमिटेड की कुल प्रबंधनाधीन परिसंपत्ति (एएमयू) 2.6 गुना की सालाना वृद्धि के साथ 30,667 करोड़ रुपये पर पहुंच गयी। ऋण वितरण 2.7 गुना बढ़कर 11,252 करोड़ रुपये हो गया। जियो पेमेंट्स बैंक की कुल आय 83 करोड़ रुपये रही। यह सालाना 7.7 गुना की वृद्धि दिखाता है। कुल जमा राशि 617 करोड़ रुपये रही जो सालाना 72 प्रतिशत अधिक है।

भारत में कृषि क्षेत्र को ऋण बीते 11 वर्षों में 4 गुना बढ़कर 32.50 लाख करोड़ रुपये हुआ

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत में कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में बीते एक दशक में तेज बढ़ोतरी हुई है और यह वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 32.50 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो कि वित्त वर्ष 2014-15 के 8 लाख करोड़ रुपए से चार गुना से अधिक है। यह जानकारी सरकार द्वारा जारी फैक्टशीट में दी गई। फैक्टशीट के मुताबिक, ग्रामीण ऋण इकोसिस्टम वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2023-24 के बीच करीब 13 प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ा है। कृषि में जमीनी स्तर पर ऋण को बढ़ावा देने के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) बैंकों को कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म लोन देने के लिए उनके संसाधनों को बढ़ाने के मकसद से रीफाइनेंस सपोर्ट देता है। फैक्टशीट में बताया गया कि औपचारिक ग्रामीण वित्त की बढ़ती पहुंच की झलक नाबार्ड के ग्रामीण आर्थिक स्थिति एवं भावना सर्वेक्षण (मई 2026) में भी देखने को मिलता है। सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 77.2 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों ने अपने उपभोग स्तर में वृद्धि की जानकारी दी, जो बढ़ती क्रय शक्ति और लगातार बनी हुई मांग को दर्शाता है। औपचारिक ऋण तक पहुंच में भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। लगभग 51 प्रतिशत परिवार केवल औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त कर रहे हैं, जबकि 27 प्रतिशत से अधिक परिवार संस्थागत और गैर-संस्थागत दोनों माध्यमों से ऋण ले रहे हैं। वर्ष 2014 में ग्रामीण क्षेत्रों में 41,464 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शाखाएं थीं। जुलाई 2025 तक इनकी संख्या 35 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 56,193 हो गई, जिससे ग्रामीण ऋण वितरण को महत्वपूर्ण मजबूती मिली। इसके अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित हैं, जिनका 700 जिलों में 22,000 से अधिक शाखाओं का नेटवर्क है। सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों ने भी दूरदराज के क्षेत्रों में गरीबों के बीच बैंकिंग की आदतों को बढ़ावा देकर संस्थागत ऋण के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरबीआई और नाबार्ड के अनुसार, सहकारी बैंकिंग नेटवर्क में 1,458 शहरी सहकारी बैंक, 34 राज्य सहकारी बैंक और 352 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सरकार का विशेष ध्यान गरीबों के लिए संचालित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर भी है, जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। यह योजना ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करती है और उनकी आय बढ़ाने तथा जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायता करती है। यह कार्यक्रम पूरे देश में लागू किया जा रहा है। 10 जुलाई 2026 तक 19.83 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह सक्रिय थे और योजना की शुरुआत से अब तक इनके माध्यम से 13.28 लाख करोड़ रुपए के ऋण का वितरण किया जा चुका है।

भारत की पहली इंजीनियरिंग बायोलॉजी स्नातक डिग्री शुरू होगी, 2035 तक बायोइकोनॉमी महाशक्ति बनने का लक्ष्य

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत में पहली बार इंजीनियरिंग बायोलॉजी की स्नातक डिग्री शुरू करने की घोषणा की है। नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता में '2035 तक भारत को अग्रणी बायोइकोनॉमी शक्ति बनाने' के रोडमैप के लॉन्च के दौरान ने डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इंजीनियरिंग बायोलॉजी भविष्य में वही भूमिका निभाएगी जो डिजिटल क्रांति में कंप्यूटर साइंस ने निभाई थी। इस नए पाठ्यक्रम के जरिए ऐसे विशेषज्ञ तैयार किए जाएंगे जो इंजीनियरिंग, जीवविज्ञान, चिकित्सा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के संगम पर काम कर सकें। उन्होंने बताया कि कई आईआईटी मेडिकल संस्थानों के साथ मिलकर इस विषय में अंतरविषयक (इंटरडिसिप्लिनरी) कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत का स्वदेशी और आत्मनिर्भर जैव-प्रौद्योगिकी (बायोटेक) इकोसिस्टम तैयार करना है। उन्होंने बताया कि देश की बायोइकोनॉमी 2014 में लगभग 10 अरब डॉलर से बढ़कर आज करीब 95 अरब डॉलर तक पहुंच गई है और 2030 तक इसके 300 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि भारत में 11,000 से अधिक बायोटेक स्टार्टअप कार्यरत हैं, जो इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ती नवाचार क्षमता का प्रमाण हैं। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि भविष्य में सिंथेटिक बायोलॉजी, एआई आधारित जैव अनुसंधान, बायो-मैन्युफैक्चरिंग, जीन थेरेपी और सीएआर-टी सेल थेरेपी जैसी तकनीकें स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा और उद्योग में बड़ा बदलाव लाएंगी। उन्होंने उद्योग, वैज्ञानिकों और स्टार्टअप्स के बीच मजबूत साझेदारी की आवश्यकता पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. राजेश एस. गोखले ने कहा कि भारत की बायोइकोनॉमी 15-18 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रही है। देश में लगभग 100 बायो-इन्क्यूबेटर और 10,000 से अधिक बायोटेक कंपनियां कार्यरत हैं। वहीं, नीति आयोग के सदस्य प्रो. गोबर्धन दास ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2035 तक भारत की बायोइकोनॉमी को लगभग 700 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। इसके लिए 50,000 करोड़ रुपये के बायोइकोनॉमी ग्रोथ फंड का प्रस्ताव भी रखा गया है।

महाराष्ट्र में ताडाली-घुगुस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी, 228 करोड़ रुपये होंगे खर्च

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के ताडाली-घुगुस रेलखंड (14 किलोमीटर) के दोहरीकरण को 228 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी है। इस परियोजना के पूरा होने से दिल्ली-चेन्नई हाई डेंसिटी नेटवर्क (एचडीएन) पर मालगाड़ियों के परिचालन में सुधार होगा और इस महत्वपूर्ण रेल मार्ग की माल ढुलाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

रेल मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, यह परियोजना रेलवे नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से स्वीकृत दोहरीकरण, तिहरीकरण, चौथी लाइन, फ्लाईओवर और बाईपास जैसी आधारभूत संरचना परियोजनाओं के तहत मंजूर की गई है। ताडाली-घुगुस रेलखंड वर्धा-बल्लारशाह रेलमार्ग का हिस्सा है, जो दिल्ली-चेन्नई हाई डेंसिटी नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण खंड है। वर्तमान में यह एकल रेललाइन है। इसके दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन अधिक सुगम होगा और बढ़ती माल परिवहन मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। रेल मंत्रालय के अनुसार, यह रेलखंड मुख्य रूप से माल ढुलाई के लिए उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से कोयला, लौह अयस्क, जिप्सम, पेट्रोलियम उत्पाद (पीओएल), रेत तथा लेटराइट राख सहित विभिन्न आवश्यक वस्तुओं का परिवहन किया जाता है।

दिल्ली के दो बड़े आयोजनों में मप्र को मिले 20,193 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव, 27592 रोजगार सृजन की संभावना

एजेंसी

भोपाल। मध्य प्रदेश ने नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स-2026 तथा इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन मध्य प्रदेश के माध्यम से निवेश आकर्षित करने में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दोनों आयोजनों में प्रदेश को ?20,193 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे लगभग 27,592 लोगों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों, उद्योगपतियों और वैश्विक ब्रांड प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश को देश का उभरता हुआ औद्योगिक एवं टेक्सटाइल हब बताया और उन्हें जनवरी 2027 में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (तद्धस्-2027) में भाग लेने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश निवेशकों को अनुकूल नीतियां, मजबूत अधोसंरचना, कुशल मानव संसाधन और त्वरित प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध करा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इन निवेश प्रस्तावों, साझेदारियों और एमओयू के माध्यम से मध्यप्रदेश देश के अग्रणी निवेश गंतव्यों में अपनी स्थिति और अधिक सुदृढ़ करेगा तथा विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

भारत टेक्स-2026 में टेक्सटाइल क्षेत्र को मिला बड़ा निवेश

मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत मंडपम में आयोजित टेक्सटाइल राउंडटेबल में प्रदेश के वस्त्र एवं परिधान उद्योग, पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, तकनीकी वस्त्र, निर्यात संवर्धन, कौशल विकास और निवेश प्रोत्साहन पर विस्तृत चर्चा हुई। इस आयोजन में ?1,592 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे लगभग 15,700 रोजगार सृजित होने की संभावना है।

दिल्ली निवेश संवाद में सात महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर

वहीं, इंटरैक्टिव सेशन के दौरान एमपीआईडीसी ने निर्यात संवर्धन, ई-कॉमर्स, वैश्विक व्यापार, एमएसएमई और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सात महत्वपूर्ण समझौतों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। साथ ही रक्षा, डेटा सेंटर, आईटी, एआई, सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन और खाद्य प्रसंस्करण सहित अनेक क्षेत्रों में निवेश अवसर प्रस्तुत किए गए।

रक्षा और डेटा सेंटर सहित कई क्षेत्रों में बड़े निवेश प्रस्ताव

दिल्ली निवेश संवाद में रक्षा, डेटा सेंटर, ट्रांसफॉर्मर निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, इंजीनियरिंग और खिलौना उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में ?18,601 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे लगभग 11,892 रोजगार सृजित होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नई दिल्ली स्थित होटल द लीला पैलेस में आयोजित इंटरएक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्यप्रदेश को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को साकार करने में मध्य प्रदेश पूरी शक्ति और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए नीति, नीयत, प्रतिभा, प्रवृत्ति, सुविधा, सामर्थ्य, ऊर्जा, उत्साह, सेवा और सुरक्षा की गारंटी लेकर आगे आया है। उन्होंने जनवरी 2027 में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 के लिए देश-विदेश के निवेशकों को आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश आज देश के सबसे तेज़ी से विकसित हो रहे औद्योगिक राज्यों में शामिल है। प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क, सुदृढ़ रेल संपर्क, 8 क्रियाशील एयरपोर्ट, 6 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, एक्सप्रेस-वे, औद्योगिक कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर और आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना उपलब्ध है। उद्योगों के लिए सवा लाख एकड़ से अधिक लैंड बैंक, पर्याप्त बिजली एवं जल की उपलब्धता तथा नए औद्योगिक क्षेत्रों, फूड पार्क, आईटी पार्क, प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है।

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पांच आतंकी ढेर

एजेंसी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने बन्नू जिले में एक खुफिया सूचना पर केंद्रित अभियान में पांच आतंकवादियों को मार गिराया। उनके पास से राइफलें और भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद हुआ है। दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, जवानों को देखते ही आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद हुई गोलीबारी में पांच संदिग्ध आतंकवादी मारे गए, जबकि कई अन्य भागने में सफल रहे। मुठभेड़ के बाद पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी मौके पर पहुंची और भाग रहे संदिग्धों को पकड़ने के लिए इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान करने की प्रक्रिया चल रही है। उनके पास से पांच कलाश्निकोव राइफल, दस मैगजीन, पांच बैंडोलियर, दो हैंड ग्रेनेड और भारी मात्रा में गोला-बारूद भी बरामद किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि आतंकवादियों के मददगारों पर भी शिकंजा कसा जाएगा।

ईरान ने अमेरिका पर युद्ध अपराध का लगाया आरोप, नागरिक ढांचे को निशाना बनाने का दावा

तेहरान। ईरान ने अमेरिका पर अपने हालिया हवाई हमलों में नागरिक ढांचे को निशाना बनाकर युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि अमेरिकी हमले संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांतों का खुला उल्लंघन हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे पर हमले कर कई युद्ध अपराध किए हैं। बयान के अनुसार, इस तरह की कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के खिलाफ है और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ईरान ने साथ ही खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों पर अपने हमलों को आत्मरक्षा का अधिकार बताते हुए उनका बचाव किया। मंत्रालय ने कहा कि ये कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद-51 के तहत ईरान के वैध आत्मरक्षा अधिकार के अनुरूप की गई। हालांकि, बयान में हाल के उन आरोपों का उल्लेख नहीं किया गया जिनमें ईरान पर वाणिज्यिक जहाजों, आवासीय इमारतों, होटलों, नागरिक हवाई अड्डों तथा ऊर्जा और जल सुविधाओं पर हमले करने के आरोप लगाए गए हैं। इनमें 3 जून को कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले और पिछले महीने बहरीन में एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाने वाली घटना भी शामिल है।

प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के संसदीय दल के उपनेता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

काठमांडू। नेपाल पुलिस ने कपिलवस्तु में उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष पर कथित हमले के मामले में प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के उपनेता अभिषेक प्रताप शाह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सांसद शाह के खिलाफ यह वारंट कपिलवस्तु के कृष्णनगर उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष सीताराम शर्मा पर कथित हमले में संलिप्तता के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद जारी किया गया। कपिलवस्तु जिला पुलिस कार्यालय के प्रवक्ता एवं पुलिस उपरीक्षक (डीएसपी) रिपेन्द्र कुमार सिंह के अनुसार, कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र-3 से निर्वाचित सांसद अभिषेक प्रताप शाह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। हाल ही में एक वीडियो सार्वजनिक हुआ था, जिसमें सांसद अभिषेक प्रताप शाह, कृष्णनगर नगरपालिका के मेयर राजत प्रताप शाह तथा 15-20 लोगों के समूह के साथ कथित रूप से सीताराम शर्मा के घर में प्रवेश कर उनके साथ मारपीट करते हुए दिखाई दिए थे। घटना के बाद सीताराम शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, जिसके बाद संघीय सांसद अभिषेक प्रताप शाह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की आगे की जांच कानून के अनुसार जारी रहेगी।

प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से राजतंत्र समर्थक नेता राजेन्द्र लिङ्देन की मुलाकात, संविधान की मूल संरचना बदलने पर सरकार को समर्थन देने के संकेत

काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने गुरुवार को प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यालय में राजेन्द्र लिङ्देन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री सचिवालय के अनुसार, बैठक में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम, देश की वर्तमान स्थिति तथा आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में राष्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टी (आरपीपी) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ तथा पार्टी की केंद्रीय समिति सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सांसद खुश्बु ओली भी उपस्थित थीं। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में लिङ्देन ने कहा कि यदि सरकार संविधान की मूल संरचना में बदलाव करने को तैयार होती है, तो आरपीपी सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन कार्यदल से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) सहित अन्य दलों के हटने का हवाला देते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि कुछ शर्तों के साथ आरपीपी सरकार के साथ सहयोग कर सकती है। लिङ्देन ने कहा, अन्य दलों का आरोप है कि सरकार गणतंत्र और संघीय व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यदि सरकार वास्तव में उसी दिशा में बढ़ना चाहती है, तो आरपीपी उसका समर्थन करने के लिए तैयार है। उन्होंने दोहराया कि आरपीपी वर्तमान गणतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय शासन व्यवस्था को बदलने के अपने पुराने रुख पर कायम है।

उन्होंने कहा, हम लगातार कहते आए हैं कि गणतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और संघीय व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। यदि सरकार मौजूदा व्यवस्था को समाप्त करने का प्रस्ताव लाती है, तो हम उसका समर्थन करेंगे।

अमेरिकी चुनाव को लेकर ट्रंप के बयान ने बढ़ाई हलचल, कमला हैरिस बोलीं-सच्चाई से ध्यान हटाना चाहते हैं राष्ट्रपति

एजेंसी

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर किए गए दावों ने देश के राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन के वोटरों का डेटा हैक करने और रूस-ईरान की सेंधमारी का आरोप लगाया। अमेरिकी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप लोगों का सच्चाई से ध्यान भटकाना चाहते हैं। दरअसल, अमेरिका में मिड टर्म का चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले देश की राजनीतिक गलियारों की हलचल तेज हो गई। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'इससे पहले कि राष्ट्रपति आज रात (स्थानीय समय गुरुवार) टेलीविजन पर झूठ और साजिश के सिद्धांत फैलाएं, आपको

यह जानना आवश्यक है: 2020 का चुनाव चोरी नहीं हुआ था. हम जीत गए और वह हार गए। 'सेव एक्ट' वोटर को दबाने का एक तरीका है। यह कंजर्वेटिव लोगों के एक बड़े एजेंडे का हिस्सा है जो लोगों से पावर छीनने की कोशिश कर रहे हैं।' उन्होंने आगे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार ने घर, स्वास्थ्य सुविधा, बच्चों की देखभाल, खाने या गैस की कीमत कम करने के लिए कुछ नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार ने अमेरिका को एक ऐसे युद्ध में डाल दिया है जो लोग नहीं चाहते। वह आपको उस सच्चाई से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।

हैरिस ने ट्रंप पर सच्चाई से ध्यान भटकाने और चुनाव में हार के डर का आरोप लगाते हुए कहा, 'राष्ट्रपति आपकी (जनता) ताकत से डरे हुए हैं और वह चाहते हैं कि आप यह मान लें कि आपके वोट का कोई मतलब नहीं है। वह चाहते हैं कि हमारे इलेक्टोरल सिस्टम पर आपका भरोसा खत्म हो जाए, इसलिए आप इस नवंबर घर पर रहें। वह जानते हैं कि अमेरिकी लोग कितने नाराज हैं और वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप वोट न दें, क्योंकि अगर लोग अपनी संख्या में वोट करेंगे, तो रिपब्लिकन हार जाएंगे।' उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि अभी हालात बहुत मुश्किल हैं और हमें बहुत काम करना है। वोटिंग एक जरूरी कदम है जिसे हम अपनी आवाज उठाने, यह साबित करने के लिए उठा सकते हैं कि हम अभी भी इस लड़ाई में हैं और इस भ्रष्ट और क्रूर सरकार पर असली रोक लगा सकते हैं। अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव नैंसी पेलोसी ने कहा कि जाहिर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति एक हारे हुए इंसान हैं। अमेरिकी सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने कहा, 'डोनाल्ड ट्रंप अभी आपके (जनता के) लिए खर्च कम करने के बजाय छह साल पहले के झूठ बोलने में अपनी शाम बिता रहे हैं।'

ईरान की पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की चेतावनी

एजेंसी

तेहरान। ईरान की सशस्त्र सेना के वरिष्ठ प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अबोलफजल शेकारची ने (स्थानीय समय) को चेतावनी दी कि अगर देश के सैन्य केंद्रों पर हमला होता है तो तेहरान पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले करेगा। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में असुरक्षा का मुख्य कारण अमेरिकी सेना की मौजूदगी है। ईरान वायर, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (आईआरआईबी) और फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। शेकारची ने आईआरआईबी पर प्रसासित साक्षात्कार में कहा कि अमेरिका और इजराइल को इस क्षेत्र में मौजूद रहने का कोई अधिकार नहीं है। होर्मुज जलडमरूमध्य ईरान के नियंत्रण में सुरक्षित है। उन्होंने इस रणनीतिक जलमार्ग में बढ़ते तनाव के लिए अमेरिकी सेना की नाकाबंदी को जिम्मेदार ठहराया। शेकारची ने पड़ोसी देशों से ईरान का सहयोग करने का आग्रह किया। प्रवक्ता ने कहा, अगर नुकसान पहुंचाया जाता है, तो क्षेत्र का सारा अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे निशाने पर होगा। उन्होंने कहा, हम दुश्मन पर ताकत के साथ हमला करेंगे। हम सालों तक लड़ सकते हैं। उनकी यह टिप्पणी ईरान के खतम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता की इसी तरह की चेतावनी के बाद आई है। खतम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ईरान की सबसे बड़ी ऑपरेशनल कमांड यूनिट है। यह सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के बीच सैन्य अभियान में तालमेल बिठाती है। खतम-अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के बयान में कहा गया है कि अमेरिका को किसी भी स्थिति में और किसी भी तरह से इस जलमार्ग में दखल देने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

ट्रंप प्रशासन की चेतावनी, अमेरिका में चुनावी डेटा पर साइबर हमले का खतरा

एजेंसी

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने हाल ही में सार्वजनिक किए गए गोपनीय खुफिया और साइबर सुरक्षा आकलनों में चेतावनी दी कि देश के मतदाता पंजीकरण डेटाबेस अब भी विदेशी साइबर हमलों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। अगर यह डेटा चोरी होता है तो उसका दुरुपयोग कई वर्षों तक किया जा सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी सुरक्षा पर दिए गए संबोधन के बाद जारी इन दस्तावेजों में कहा गया कि मतदाता पंजीकरण डेटाबेस विदेशी खुफिया एजेंसियों और साइबर हमलावरों के लिए सबसे आकर्षक लक्ष्यों में से एक हैं। इनका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालना और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लोगों का भरोसा कमजोर करना हो सकता है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में अमेरिका के सभी 50 राज्यों के मतदाता पंजीकरण सिस्टम को हैक करने की कोशिश की गई। इनमें से कम से कम 20 राज्यों में साइबर हमलावरों को सेंध लगाए।

रिपोर्ट में कहा गया, 'राज्य स्तर के मतदाता पंजीकरण डेटाबेस विदेशी विरोधी देशों के लिए बेहद आकर्षक लक्ष्य हैं।' इसमें यह भी चेतावनी दी गई है कि मतदाताओं की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी लीक होने का खतरा सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके प्रभाव लंबे समय तक रह सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, चोरी किए गए मतदाता डेटा का इस्तेमाल डाक मतपत्र के लिए फर्जी आवेदन करने, मतदाता पंजीकरण रिकॉर्ड में बदलाव करने, मतदान केंद्र बदलने या मतदाता का नाम सूची से हटाने जैसे कामों में किया जा सकता है।

इस आकलन रिपोर्ट में वर्ष 2016 के बाद से चुनावी ढांचे पर हुए कई साइबर हमलों का भी जिक्र किया गया। इनमें वोटर रजिस्ट्रेशन डेटाबेस की जांच करने की रूस की कोशिशें, वोटर रजिस्ट्रेशन की जानकारी हासिल करने का ईरान का प्रयास और चुनाव से जुड़े नेटवर्क एवं आम लोगों के लिए उपलब्ध वोटर डेटा को निशाना बनाने वाली चीन की संदिग्ध साइबर गतिविधियां शामिल हैं।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि हाल ही में सार्वजनिक किए गए खुफिया दस्तावेज यह साबित करते हैं कि अमेरिका लंबे समय से जानता था कि उसकी चुनावी व्यवस्था विदेशी साइबर खतरों के संपर्क में है।

छह देशों के बाद जयशंकर ने ज्यूरिख में भारतीय राजदूत से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों पर हुई बातचीत

एजेंसी

ज्यूरिख। स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत मृदुल कुमार ने ज्यूरिख एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की। जयशंकर छह देशों के दौरे के बाद नई दिल्ली लौट रहे थे। स्विट्जरलैंड में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बताया, 'राजदूत मृदुल कुमार ने ज्यूरिख एयरपोर्ट पर ट्रांजिट के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर का गर्मजोशी से स्वागत किया। वह कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, अमेरिका और बेल्जियम के सफल दौरे से लौट रहे थे। इस मौके पर राजदूत ने उन्हें भारत-स्विट्जरलैंड के रिश्तों में हाल की प्रगति और दोनों देशों के बीच बढ़ती उच्च-स्तरीय मुलाकातों की जानकारी भी दी।' विदेश मंत्री जयशंकर ने बुधवार को ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ (ईयू) की स्टार्टअप, रिसर्च और इनोवेशन कमिश्नर एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने स्वच्छ और हरित ऊर्जा तकनीकों, इनोवेशन हब, स्टार्टअप्स और 'होराइजन यूरोप' से जुड़ने के अवसरों पर चर्चा की। इस बैठक में बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत प्रणय वर्मा और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

एस. जयशंकर ने बेल्जियम के विदेश मंत्री मैक्सिम प्रेवोट से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने राजनीति, अर्थव्यवस्था, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, लोगों की आवाजाही (मोबिलिटी) और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग की समीक्षा की। साथ ही बंदरगाह, समुद्री क्षेत्र, सेमीकंडक्टर और सप्लाई चेन को अधिक मजबूत और सुरक्षित बनाने के नए अवसरों पर भी चर्चा हुई। यह बातचीत बुधवार को ब्रुसेल्स में आयोजित पहले इंडिया-बेल्जियम स्ट्रेटेजिक डायलॉग के दौरान हुई। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया समेत दुनिया के कई अहम मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। बैठक के बाद जयशंकर ने 'एक्स' पर लिखा, 'आज ब्रुसेल्स में बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रेवोट के साथ पहले इंडिया-बेल्जियम स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सह-अध्यक्षता की। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। आज की बातचीत से भारत, बेल्जियम और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी को और आगे बढ़ाने की हमारी इच्छा साफ दिखाई दी।'

ट्रंप सरकार का कट्टर वामपंथी समूहों के खिलाफ बड़ा एक्शन, अमेरिका ने लगाई वीजा पर रोक

एजेंसी

नई दिल्ली। ट्रंप प्रशासन ने अपनी आव्रजन नीति को और सख्त करते हुए उन विदेशी नागरिकों के खिलाफ नई वीजा प्रतिबंध नीति की घोषणा की है, जिन पर प्रशासन द्वारा वामपंथी आतंकवादी संगठनों या उनसे जुड़े समूहों का समर्थन करने का आरोप है। यह घोषणा ऐसे समय में की गई, जब अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो ने 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों की मंत्रीस्तरीय बैठक की शुरुआत की। बैठक का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक आतंकवाद के दोबारा उभरते खतरे से निपटने के लिए वैश्विक समन्वय को मजबूत करना बताया गया। अमेरिकी विदेश विभाग के एक बयान के अनुसार, नई नीति के तहत उन विदेशी नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी, जिन्होंने आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन या उन्हें उकसाया हो, हिंसक आपराधिक गतिविधियों का समर्थन किया हो अथवा प्रशासन द्वारा वामपंथी

आतंकवादी करार दिए गए समूहों और उनसे जुड़े संगठनों के लिए वित्तपोषण, भर्ती या लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराई हो। इसके अलावा हिंसक गतिविधियों के उद्देश्य से ऐसे नेटवर्कों के समन्वय में सहायता करने वालों को भी इस दायरे में रखा जाएगा। रुबियो ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य अमेरिका की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी, हिंसक और आपराधिक वामपंथी नेटवर्कों को वित्तपोषण, भर्ती, उकसाने या अन्य प्रकार की सहायता देने वाले विदेशी नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस नीति से उन वीजा मार्गों को बंद किया जा सकेगा, जिनका इस्तेमाल ऐसे संगठन अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने, आर्थिक स्थिरता को कमजोर करने और अमेरिकी भूमि पर हिंसक गतिविधियों के समन्वय के लिए कर सकते हैं। यह कार्रवाई इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की धारा 212(ए)(3)(सी) के तहत की जा रही है।

वीजा प्रतिबंधों की घोषणा ऐसे समय हुई, जब अमेरिकी विदेश विभाग ने राजनीतिक आतंकवाद के दोबारा उभरने के मुद्दे पर मंत्रीस्तरीय बैठक आयोजित की। इसमें पश्चिम गोलार्ध, यूरोप और एशिया की सरकारें एक साथ आईं ताकि कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जा सके, जानकारी साझा करने के तरीकों को मजबूत किया जा सके और सरकार के मुताबिक बढ़ते हुए सीमा-पार के खतरे के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग को बढ़ाया जा सके।

गैंगस्टर नीतीश कौशल को अमेरिका में एफबीआई ने गिरफ्तार किया

एजेंसी

वाशिंगटन। अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने भारतीय गैंगस्टर्स के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एफबीआई ने कहा कि गैंगस्टर नीतीश कौशल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो ने इससे पहले उसका नाम अपनी मोस्ट वांटेड सूची में शामिल किया था। उस पर हत्या, अपहरण, ड्रग तस्करी, जबरन वसूली, हथियारों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी जैसे अपराधों में शामिल रहने का आरोप है।

संघीय जांच ब्यूरो ने एक्स हैंडल में सूचना साझा की कि गैंगस्टर नीतीश कौशल को वरमोंट में गिरफ्तार कर लिया गया है। एफबीआई ने लोगों से अपील की है कि आपराधिक गतिविधियों की जांच से जुड़े अपराधों के लिए वांछित अन्य भगोड़ों का पता लगाने में उसकी मदद करें। एफबीआई ने मंगलवार को नीतीश कौशल को एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन का गुर्गा घोषित किया था।

ब्यूरो के अनुसार, यह संगठन हत्या, अपहरण, ड्रग तस्करी, जबरन वसूली, हथियारों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी जैसे अपराधों में सक्रिय है। यह संगठन भारत के पंजाब में पनपा और बाद में कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और अन्य जगहों पर काम करने लगा।

एफबीआई के शिकंजे में आया गैंगस्टर नीतीश कौशल भगवानपुरिया गैंग के लिए काम करता रहा है। एफबीआई ने कहा कि नीतीश भारतीय नागरिक है। लॉस एंजिल्स में कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की अमेरिकी जिला अदालत ने 25 जून को नीतीश कौशल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। एफबीआई की यह कार्रवाई 'ऑपरेशन हार्ड बॉल' के तहत की गई है।

अमेरिकी चुनाव प्रणाली पर ट्रंप का बड़ा कदम, चीनी हस्तक्षेप से जुड़े खुफिया रिकॉर्ड जारी करने के निर्देश

एजेंसी

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुफिया और कानून प्रवर्तन से जुड़े दस्तावेजों के एक बड़े संग्रह को सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। ट्रंप का दावा है कि ये दस्तावेज अमेरिकी मतदाताओं के डेटा में चीनी सेंधमारी, चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप के खतरों और देश की चुनावी व्यवस्था की गंभीर कमियों को उजागर करते हैं। ट्रंप ने गुरुवार रात देशभर में प्रसारित एक भाषण में कहा, 'आज रात, मैं हमारे चुनावी इंफ्रास्ट्रक्चर में मौजूद चौंकाने वाली कमियों को उजागर करने वाली अहम खुफिया जानकारी को तुरंत सार्वजनिक करने और जारी करने की घोषणा कर रहा हूं।' ट्रंप ने कहा कि ये दस्तावेज़ व्हाइट हाउस की 'गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी टास्क फोर्स' ने तैयार किए थे और राष्ट्रपति के 'इंटेलिजेंस एडवाइजरी बोर्ड' तथा वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों की मदद से इनकी समीक्षा की गई थी।

उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड्स के पहले समूह से पता चला है कि चीन ने 22 करोड़ अमेरिकी वोटरों की फाइलें हासिल कर ली थीं। इन फाइलों में नाम, पते, टेलीफोन नंबर, राजनीतिक जुड़ाव और ऐसी अन्य जानकारी शामिल थी, जिसका इस्तेमाल चुनाव से जुड़े कामों में किया जा सकता था।

व्हाइट हाउस की एक अलग टास्क फोर्स के बयान में कहा गया कि राज्य-विशेष जुड़ाव के बिना 20 करोड़ से अधिक वोटर रिकॉर्ड्स की सुरक्षा में सेंध लगी थी, जबकि कम से कम 18 राज्यों से जुड़े रिकॉर्ड्स भी प्रभावित हुए थे। बयान में सार्वजनिक रूप से 16 क्षेत्रों की पहचान की गई, जिनमें अलास्का, अर्कांसस, कोलोराडो, कनेक्टिकट, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, मैरीलैंड, मिशिगन, न्यूयॉर्क, नॉर्थ कैरोलिना और ओहियो शामिल हैं।

ट्रंप ने इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अधिकारियों पर चीन की गतिविधियों के बारे में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया और कहा कि उनके पहले कार्यकाल के दौरान उन्हें यह जानकारी नहीं दी गई थी।

उन्होंने 'ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस', जस्टिस डिपार्टमेंट, एफबीआई और सीआईए से इस बात की जांच करने को कहा कि कथित तौर पर यह जानकारी क्यों छिपाई गई। उन्होंने यह भी मांग की कि किसी भी गलत काम में शामिल अधिकारियों को नौकरी से निकाला जाए और जहां जरूरी हो, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए।

जारी किए गए रिकॉर्ड में ऐसी रिपोर्टें शामिल हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि चीन ने ट्रंप को राजनीतिक रूप से कमजोर करने, अमेरिकी बिजनेस लीडर्स और पत्रकारों को प्रभावित करने और अमेरिका में नस्लीय, आर्थिक, इमिग्रेशन और पार्टी-आधारित मतभेदों का फायदा उठाने की कोशिश की।

नेपाल और भारत अतिरिक्त हवाई प्रवेश मार्गों पर फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत

एजेंसी

काठमांडू। नेपाल और भारत अतिरिक्त द्विपक्षीय हवाई प्रवेश मार्गों पर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए सहमत हो गए हैं। लगभग एक दशक बाद पोखरा और भैरहवा में नेपाल के दो नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के संचालन के लिए यह वार्ता अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त हवाई प्रवेश मार्ग लंबे समय से नेपाल की एक प्रमुख मांग रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में लगभग 90 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय उड़ानें सिमरा के ऊपर एक ही भीड़भाड़ वाले प्रवेश बिंदु (एंट्री पॉइंट) से देश में प्रवेश करती हैं। भारत ने नेपाल के पश्चिमी और पूर्वी गलियारों से सीधे, कम ऊंचाई वाले प्रवेश मार्ग अब तक नहीं दिया है। भारत ने इसके लिए गोरखपुर हवाई अड्डे (एयर बेस) सहित संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठानों से संबंधित सुरक्षा चिंताओं के साथ-साथ हवाई यातायात प्रबंधन की जटिलताओं का हवाला दिया है।

दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त सीमा पार

हवाई प्रवेश मार्गों पर चर्चा और बातचीत के लिए अगस्त में मिलने की उम्मीद है। हालांकि, बैठक की तारीख और स्थान अभी तय होना बाकी है। इस मुद्दे पर काठमांडू में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल और भारत के विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनु महावर के बीच एक बैठक के दौरान चर्चा हुई। मुनु महावर ऊर्जा सचिव स्तर की 13वीं नेपाल-भारत संयुक्त संचालन समिति (ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी) की बैठक में भाग लेने के लिए नेपाल में हैं, जो बुधवार को पोखरा में संपन्न हुई। विदेश मंत्री खनाल के साथ बैठक के दौरान, खनाल ने भारत से लंबे समय से लंबित तकनीकी समिति की बैठक बुलाने का आग्रह किया, जिसका काम अतिरिक्त हवाई मार्गों के लिए नेपाल के अनुरोध पर चर्चा करना है। खनाल के मुताबिक महावर ने आश्वासन दिया है कि बैठक अगले महीने होगी। तकनीकी स्तर का तंत्र अतिरिक्त हवाई प्रवेश मार्गों के लिए नेपाल के अनुरोध में आने वाली बाधाओं की समीक्षा करेगा।।

नेपाल की बालेन्द्र सरकार का एक रुपये के सिक्के से विवादित नक्शा हटाने का फैसला

एजेंसी

काठमांडू। बालेन्द्र शाह सरकार ने 1 रुपये के सिक्के से नेपाल का विवादित नक्शा हटाकर उसकी जगह मुस्ताङ स्थित लो घ्याकर (घर) गुम्बा की आकृति अंकित करने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद की आज हुई बैठक में नेपाल राष्ट्र बैंक को 1 और 2 रुपये के नए सिक्के ढालने (टकसाल में तैयार करने) की

स्वीकृति दी गई।नेपाल राष्ट्र बैंक के अधिकारियों के अनुसार नए सिक्कों का मौजूदा आकार, वजन, धातु और डिजाइन बदला जाएगा। इसी क्रम में 1 रुपये के सिक्के पर बने नेपाल के नक्शे को हटाकर आठवीं शताब्दी के ऐतिहासिक लो घ्याकर गुम्बा का चित्र अंकित करने का निर्णय लिया गया है। सरकारी अधिकारियों ने तर्क दिया कि सिक्के का आकार छोटा होने के कारण उस पर नेपाल का नक्शा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना कठिन है। नेपाल के विवादित नक्शे अंकित सिक्के निकालने का निर्णय तत्कालीन केपी शर्मा ओली की सरकार ने किया था। लेकिन बालेन्द्र सरकार ने उस विवादित नक्शे को हटा कर भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने का संकेत दिया है।

राष्ट्रपति ट्रंप का 2020 के चुनाव को लेकर बड़ा दावा, राजनीतिक दखल देने के लिए चीन ने चलाया अभियान

एजेंसी

वाशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनाव में दखल देने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजिंग उनके राष्ट्रपति पद को कमजोर करना चाहता है और लाखों अमेरिकी वोटरों का रिकॉर्ड हासिल करना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि वह अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर अपनी गतिविधियों को छिपाना चाहता है। व्हाइट हाउस से राष्ट्र के नाम टेलीविजन पर प्रसारित संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव सुरक्षा से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को तत्काल प्रभाव से सार्वजनिक करने की घोषणा की। उन्होंने दावा किया कि इन दस्तावेजों से अमेरिका की चुनावी व्यवस्था में चौंकाने वाली कमियां सामने आई हैं और इनमें वर्षों तक अमेरिकी राजनीति को प्रभावित करने के लिए चीन के कथित प्रयासों का भी विवरण है। ट्रंप ने कहा, 'पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने चुनावी डेटा में इतिहास की सबसे बड़ी सेंध लगाई, जिसके परिणामस्वरूप चीन ने अवैध रूप से 22 करोड़ अमेरिकी मतदाताओं की फाइलें हासिल कर लीं।'

उन्होंने दावा किया कि इन रिकॉर्ड्स के अनुसार, चुराए गए डेटा में मतदाताओं के नाम, पते, फोन नंबर, राजनीतिक दल की प्राथमिकता और अन्य व्यक्तिगत जानकारियां शामिल थीं, जिनका इस्तेमाल मतदाता पंजीकरण कराने और अन्य कथित अवैध गतिविधियों के लिए किया जा सकता था। ट्रंप ने आरोप लगाया कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को पहली बार 2020 में पता चला कि 18 राज्यों में करोड़ों वोटर रिकॉर्ड चीन ने खरीदे, चुराए या हैक किए थे। हालांकि, राष्ट्रपति ने यह आरोप भी लगाया कि एजेंसी ने ये जानकारी प्रेसिडेंट या कांग्रेस को नहीं दी। उन्होंने कहा, 'उन्होंने मुझे या राष्ट्रपति के तौर पर किसी और को यह नहीं बताया और हमारी जानकारी के मुताबिक, उन्होंने कांग्रेस को भी नहीं बताया।'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीआईए की हाल ही में सार्वजनिक की गई रिपोर्ट का भी जिक्र किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बीजिंग ने 2018 के अमेरिकी मिडटर्म और 2020 के राष्ट्रपति चुनाव, दोनों पर असर डालने की कोशिश की थी।

ट्रंप के मुताबिक, एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया था कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिसी अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ सभी घरेलू और विदेशी एलिमेंट्स का फायदा उठाना था, ताकि यूएस प्रेसिडेंट के वोट कम किए जा सकें और उन्हें इस्तीफा देने या उनके दोबारा चुनाव को रोकने के लिए मजबूर किया जा सके। उन्होंने आगे दावा किया कि एक और इंटेलिजेंस असेसमेंट से यह नतीजा निकला कि चीन की रणनीति का मकसद अमेरिका के राष्ट्रपति में लोगों के भरोसे को कम करना था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इंटेलिजेंस में यह भी आरोप लगाया गया है कि बीजिंग ने बड़ी अमेरिकी कंपनियों के साथ कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके बिजनेस लीडर्स को अपनी सरकार का विरोध करने के लिए मनाने की कोशिश की। उन्होंने आगे दावा किया कि रिकॉर्ड में कहा गया है कि चीनी सरकार उन अमेरिकी पत्रकारों की पहचान करना चाहती थी जिन्होंने उनकी आलोचना की थी और उन्हें और नकारात्मक रिपोर्ट बनाने के लिए पैसे दिए। ट्रंप ने कहा, 'चीनी सरकार चाहती थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति अगला चुनाव हार जाएं। बीजिंग ने चीनी सामान पर उनके सरकार के टैरिफ और उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का विरोध किया था।' राष्ट्रपति ने यह भी आरोप लगाया कि 2020 की एफबीआई की रॉ इंटेलिजेंस से पता चला है कि चीनी गतिविधियों में जो बाइडेन के लिए गैर-कानूनी बैलेट बनाने की कोशिश शामिल थी।

page 1 and 8 July 18_page 1 Mar 25 final ds.qxd 7/18/2026 12:25 AM Page 2

स्वतंत्रता दिवस 2026 समारोह की तैयारियों की डीसी सांबा ने समीक्षा

सांबा, 17 जुलाई। उपायुक्त (डीसी) सांबा आयुषी सूदन ने आज जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में स्वतंत्रता दिवस 2026 समारोह के गरिमापूर्ण, सफल एवं सुचारु आयोजन के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने रानी सुचेत सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम, सांबा में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को अपने-अपने कार्य समय रहते पूरा करने तथा बेहतर समन्वय के साथ आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने आयोजन स्थल तथा उसके आसपास स्वच्छता और सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत विकास विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति तथा सभी प्रमुख सरकारी भवनों, पुलों और मुख्य आयोजन स्थल पर आकर्षक रोशनी की व्यवस्था करने को कहा।

जल शक्ति विभाग को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, जबकि संबंधित विभाग को कार्यक्रम के सुचारु संचालन के लिए बेहतर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली (पब्लिक एड्रेस सिस्टम) स्थापित करने को कहा गया।

शिक्षा विभाग तथा युवा सेवा एवं खेल विभाग को सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मार्च पास्ट रिहर्सल और अन्य औपचारिक गतिविधियों का समन्वय करने के निर्देश दिए गए, ताकि जिले की देशभक्ति की भावना और सांस्कृतिक विविधता का प्रभावी प्रदर्शन हो सके। उपायुक्त ने सभी सरकारी कार्यालयों एवं सार्वजनिक संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के दौरान भारतीय ध्वज संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने पुलिस विभाग को व्यापक सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और पार्किंग योजना तैयार करने के निर्देश दिए ताकि प्रतिभागियों और आम जनता की आवाजाही सुचारु बनी रहे। इसके अलावा समारोह के दौरान उत्कृष्ट व्यक्तियों के सम्मान एवं पुरस्कार वितरण की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आयोजन स्थल पर चिकित्सा दल, एम्बुलेंस तथा आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं सहित सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को बैठने की व्यवस्था, मंच सजावट, बैरिकेडिंग, अल्पाहार, अग्नि सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

शामली व कैराना की डेमोग्राफी बदल रहे थे जिन्ना के उपासक: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने शामली, थानाभवन व कैराना विधानसभा क्षेत्रों की 581 करोड़ रुपये से अधिक की 89 परियोजनाओं का किया लोकार्पण/शिलान्यास

10 साल पहले आतंक व भय का प्रतीक था शामली, अब यहां गन्ने की मिठास और एक्सप्रेसवे की 'त्रिवेणी' है: सीएम योगी*

2017 के पहले 12 बजे तक सोने वाली और अब भोर में 4 बजे से काम करने वाली सरकार- सीएम योगी

कांवड़ यात्रा में अनुशासनहीनता स्वीकार नहीं, उपद्रव का प्रयास करने वाले को कान पकड़कर बाहर कर दें: मुख्यमंत्री

लखनऊ, 17 जुलाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी व कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जिन्ना के उपासक लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे और इसीलिए कैराना व कांधला से पलायन हो रहा था। उन्होंने स्थानीय नागरिकों को चेताया कि जिन्ना के अनुयायियों को जब भी मौका मिलेगा, वे आपको क्षेत्र व जाति के नाम पर बांटेंगे। विकास कार्यों में लूट-खसोट करेंगे। बेटी-व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाएंगे। इनसे लगातार सतर्क रहना है।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को कैराना, शामली व थानाभवन विधानसभा क्षेत्र की 581 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 89 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास करने के उपरांत जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने लोकार्पण व शिलान्यास की गई योजनाओं का विवरण देते हुए गत 10 वर्ष में शामली, थानाभवन व कैराना में आए सकारात्मक बदलाव की भी चर्चा की।

कैराना व शामली का आध्यात्मिकता, संस्कृति व आजादी में योगदान

सीएम योगी ने कहा कि 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के धर्मयुद्ध में जाने से पहले लीलाधारी प्रभु श्रीकृष्ण ने हनुमान टीले में आकर विश्राम किया था और यहां के पवित्र जल को ग्रहण किया था। शामली व कैराना ने 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर में ब्रिटिश हुकूमत की चूलों को हिला दिया था। कैराना घराने से पं. भीमसेन जोशी ने शास्त्रीय संगीत की परंपरा को नई ऊंचाई दी।

सीएम ने कहा कि 10 साल पहले लोग पूछते थे कि आतंक-भय का प्रतीक शामली जनपद कहां है। शामली, कैराना-कांधला से पलायन होता था, यहां गुंडागर्दी होती थी। कोई सुरक्षित नहीं था। शरारत के तहत डेमोग्राफी को बदलने की साजिश हो रही थी। अब यहां के गन्ने की मिठास प्रसिद्ध है। पीएम मोदी जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार शामली की गति को प्रगति में बदल रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शामली अब दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, शामली-अंबाला एक्सप्रेसवे और गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे का संगम बन चुका है। यहां की युवा पीढ़ी की ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक दिशा में किया गया तो आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर व सुरक्षा का यह बेहतर माहौल शामली को एनसीआर के सबसे धनी व समृद्ध जनपदों में खड़ा कर देगा। शामली वाले 10 साल पहले बिजली के लिए तरसते थे, लेकिन आज शामली 400 केवीए विद्युत स्टेशन के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति का माध्यम बना है। 10 साल पहले मेडिकल सुविधाएं नदारद थीं। लेकिन, कोरोना महामारी में दिल्ली व आसपास के लोग इलाज कराने शामली के हॉस्पिटलों में पहुंचे।

सीएम ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों चौधरी जयंत सिंह, वीरेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल, पूर्व मंत्री सुरेश राणा के कार्यों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत में चौधरी चरण सिंह के बाद चीनी मिलों की स्थिति में सुधार व पुनरोद्धार का बीड़ा 2017 में सुरेश राणा ने उठाया था। 2007 से 2017 के बीच तत्कालीन सरकारों में 29 चीनी मिलें बंद हुईं। 21 मिलें औने-पौने दाम पर बेची गईं। 2017 में सुरेश राणा ने मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली तो मैंने पूछा कि अब मिलें बिकेंगी तो नहीं, तब उन्होंने कहा था कि इन मिलों को वापस लेकर चलाएंगे। आज 122 चीनी मिलें चल रही हैं और किसानों को समय से भुगतान हो रहा है। अब गन्ना किसानों को 400 रुपये कुंतल दाम मिल रहा है। यूपी चीनी, गन्ना व एथेनॉल उत्पादन में नंबर एक है। यह प्रगति किसानों की समृद्धि का कारक बनी है।

सीएम योगी ने कहा कि विकास का विकल्प नहीं हो सकता। हम किसानों के उपासक हैं, जिन्होंने गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाया। हमने भी चीनी मिलों के माध्यम से उन्हें गन्ना मूल्य का भुगतान करा के दिखा दिया। शामली की खुशहाली और थानाभवन-कैराना का विकास देख लगता है कि सार्वजनिक जीवन में आना सफल हुआ है। पिछली बार मैंने यहां के स्कूलों का दौरा किया था। यूपी-सीबीएसई बोर्ड की मेरिट सूची में शामली के बच्चों का नाम देखा तो उन्हें लखनऊ बुलाया। वे बच्चे भी बता रहे थे कि अब डर नहीं लगता, क्योंकि अपराधी जानता है कि हिमाकत की तो जेल या जहन्नुम में ही जगह मिलेगी।

स्थानीय समाचार

पीडब्ल्यूडी के एक सहायक अभियंता को रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई ने किया गिरफ्तार

डोडा, 17 जुलाई (हि.स.)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यान्वयन हेतु तैनात पीडब्ल्यूडी के एक सहायक अभियंता को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है।

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने 16 जुलाई, 2026 को एक शिकायत के आधार पर उक्त आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि थथरी से काठवा (जिला डोडा) को जोड़ने वाली पीएमजीएसवाई सड़क परियोजना के निर्माण के दौरान शिकायतकर्ता के घर को नुकसान पहुंचा था और शिकायतकर्ता लगभग 10 लाख रुपये के मुआवजे का हकदार था।

यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी सहायक अभियंता ने मुआवजे की राशि की प्रक्रिया और जारी करने के लिए 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। बातचीत के बाद आरोपी शिकायतकर्ता से 30,000 रुपये की रिश्वत लेने के लिए सहमत हो गया।

सीबीआई ने जाल बिछाकर आरोपी को शिकायतकर्ता से 30,000 रुपये की रिश्वत मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा।सीबीआई द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है।

जम्मू-कश्मीर में कारोबार सुगमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर मुख्य सचिव का जोर

श्रीनगर, 17 जुलाई। मुख्य सचिव अतल डुल्लू ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर कारोबार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) और जीवन सुगमता (ईज ऑफ लिविंग) को बढ़ावा देने के लिए देश के अग्रणी राज्यों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों की समीक्षा की। बैठक का उद्देश्य इन सुधारों की जम्मू-कश्मीर में प्रभावी क्रियान्वयन की संभावनाओं का आकलन करना था।

बैठक में विभिन्न प्रशासनिक सचिवों तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की शुरुआत में मुख्य सचिव को महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक एवं नियामक सुधारों पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। इसमें प्रक्रियाओं के सरलीकरण, डिजिटल प्रशासन, नियामकीय सुधारों तथा नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण के माध्यम से निवेश और कारोबार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की पहल की जानकारी दी गई। प्रस्तुति में दोनों राज्यों द्वारा अपनाए गए अनेक सुधारों का उल्लेख किया गया। इनमें नियामकीय अनुपालनों में कमी, अनावश्यक प्रक्रियाओं का उन्मूलन, सरकारी सेवाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण, सिंगल विंडो प्रणाली को मजबूत बनाना, निरीक्षण व्यवस्था का सरलीकरण, छोटे नियामकीय अपराधों का अपराधमुक्तिकरण, निवेशकों के लिए सुविधा तंत्र, समयबद्ध सेवा वितरण, भूमि एवं निर्माण संबंधी स्वीकृतियों का सरलीकरण तथा प्रौद्योगिकी आधारित प्रशासनिक व्यवस्था शामिल हैं।

बैठक में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी), जिला बीआरएपी, विनियमन में ढील संबंधी पहलों तथा जन विश्वास ढांचे के अंतर्गत किए गए सुधारों की भी जानकारी दी गई। प्रस्तुत सुधारों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि जम्मू-कश्मीर ने पिछले कुछ वर्षों में अनेक प्रशासनिक सुधार लागू किए हैं, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप राष्ट्रीय स्तर पर सफल सिद्ध हो चुकी सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को अपनाकर प्रशासनिक बदलाव की गति और तेज करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कारोबार सुगमता के साथ-साथ जीवन सुगमता से जुड़े सुधारों पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि नागरिकों को सरकारी सेवाएं बिना किसी अनावश्यक परेशानी के उपलब्ध हों, प्रक्रियागत देरी कम हो तथा लोगों की संतुष्टि में वृद्धि हो।

कठुआ पुलिस की कार्रवाई-634 ग्राम गांजा बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार, 10 लीटर देसी शराब भी जब्त

कठुआ, 17 जुलाई (हि.स.)। नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत कठुआ पुलिस ने नशे और अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार पुलिस थाना लखनपुर की टीम ने एनएचडब्ल्यू मग्गर खड्ड पर नाका ड्यूटी के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से करीब 634 ग्राम गांजा जैसा पदार्थ बरामद किया गया। आरोपी की पहचान श्रीतेश दयाल पुत्र राम दयाल निवासी वार्ड नंबर 11 मोहतारा जिला बलोदा (छत्तीसगढ़) के रूप में हुई है। इस संबंध में थाना लखनपुर में एफआईआर नंबर 76/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

वहीं दूसरी कार्रवाई में पुलिस थाना राजबाग की टीम ने चब्बे चक क्षेत्र में छापेमारी कर करीब 10 लीटर अवैध देसी शराब बरामद की। इस दौरान राज कुमार और सुशील कुमार पुत्र सोम राज निवासी चक ड्राब खान तहसील व जिला कठुआ को मौके पर गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ एफआईआर नंबर 163/2026 धारा 48(ए) आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसएसपी कठुआ मोहीता शर्मा ने बताया कि जिले में नशे और अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

सलाल डैम के गेट खोले गये, लोगों से अपील नदियों, नहरों, नालों आदि के नजदीक न जाएं

जम्मू, 17 जुलाई (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जनता के लिए खास सूचना जारी की है। जारी की गई इस सूचना के अनुसार आज से सलाल डैम के गेट खोले गये हैं। इसके चलते नदियों, नालों आदि का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। इसी के चलते प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदियों, नहरों, नालों आदि के नजदीक न जाएं और जलस्तर बढ़ने के खतरे के चलते सावधानी बरतें। जानकारी के मुताबिक, प्रशासन द्वारा जारी इस सूचना में लिखा गया है कि आज अरनास, नारलू, थनपाल, घडी, धरण और आसपास के गांवों में आम जनता को सूचित करने के लिए एक सार्वजनिक घोषणा की गई कि सलाल बांध परियोजना के सभी गेट 17 जुलाई 2026 से 26 जुलाई 2026 तक खोले जाएंगे। निवासियों को बताया जा रहा है कि बांध के गेट खुलने से चिनाब नदी के जल स्तर में अचानक वृद्धि हो सकती है। उन्हें सलाह दी गई कि वे इस अवधि के दौरान नदी में या उसके किनारों पर न जाएं और अपने मवेशियों को चराने या पानी पिलाने के लिए नदी के पास न लेकर जाएं।

पुलिस ने 2 लापता महिलाओं को परिवार से मिलाया

कठुआ, 17 जुलाई (हि.स.)। कठुआ पुलिस ने नगरी और बसोहली क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो लापता महिलाओं को खोजकर सकुशल उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पहले मामले में 12 जुलाई को सल्लन बिलावर निवासी अशोक सिंह ने अपनी बेटी प्रिया सुम्बेरिया के लापता होने की शिकायत पुलिस पोस्ट नगरी (थाना कठुआ) में दर्ज करवाई थी। पुलिस टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए युवती को ढूंढ निकाला और परिवार को सौंप दिया। दूसरे मामले में 9 जुलाई को शीतल नगर बसोहली निवासी शौकत अली ने अपनी बेटी शहनाज अख्तर के लापता होने की रिपोर्ट थाना बसोहली में दर्ज कराई थी।

पद्दर उपमंडल में 2,000 से अधिक लोगों को मिला स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ

किश्तवाड़, 17 जुलाई- दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच मजबूत करने की दिशा में जिला प्रशासन किश्तवाड़ ने द हंस फाउंडेशन के सहयोग से पद्दर उपमंडल में आयोजित मेगा स्वास्थ्य शिविरों का सफलतापूर्वक समापन किया। इन शिविरों से 2,000 से अधिक लोगों को लाभ मिला मीडिया को जानकारी देते हुए उपायुक्त किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य शिविरों के दौरान पद्दर उपमंडल के 100 से अधिक गांवों को कवर किया गया तथा उपमंडल की लगभग 90 प्रतिशत पंचायतों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई गईं। उन्होंने बताया कि शिविरों में लोगों को नि:शुल्क सामान्य स्वास्थ्य जांच, नेत्र परीक्षण, आवश्यक दवाइयां और चश्मे उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा लगभग 78 मरीजों की सफल मोतियाबिंद सर्जरी की गई, जिससे उन्हें दोबारा दृष्टि प्राप्त हुई। उपायुक्त ने कहा कि पद्दर क्षेत्र के लोगों ने द हंस फाउंडेशन की समर्पित एवं मिशन आधारित कार्यशैली की सराहना की है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने फाउंडेशन से एक और स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने का आग्रह किया है ताकि जो लोग इस बार लाभ नहीं ले सके, उन्हें भी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने श्री भोलेनाथ जी एवं माता मंगला जी के नेतृत्व में कार्य कर रही द हंस फाउंडेशन का दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने में दिए गए योगदान के लिए आभार व्यक्त किया।

उपायुक्त ने अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त पवन कोतवाल तथा स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय कुमार भट्ट, बीएमओ पद्दर डॉ. कृष्ण सिंह कटोच, चिकित्सा अधिकारियों, पैरामेडिकल स्टाफ और शिविर के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी सराहना की।

फिक्की फ्लो जेकेएल ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए नि:शुल्क नेल आर्ट प्रशिक्षण शुरू किया

जम्मू, 17 जुलाई। फिक्की फ्लो जम्मू, कश्मीर एवं लद्दाख (जेकेएल) ने महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास की दिशा में अपनी निरंतर पहल के तहत स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) से जुड़ी महिलाओं के लिए **नि:शुल्क नेल आर्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रमका आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए सक्षम बनाना है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन फिक्की फ्लो जेकेएल की नई सदस्य तथा **अभिराए नेल आर्ट स्टूडियोकी संस्थापक **अश्वी महाजनद्वारा किया जा रहा है। वह अपनी पेशेवर विशेषज्ञता पूरी तरह नि:शुल्क उपलब्ध करा रही हैं।

इस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों को नेल आर्ट से जुड़े व्यावहारिक और बाजार की मांग के अनुरूप कौशल प्रदान करना है, ताकि वे स्वरोजगार अपनाने, स्वतंत्र रूप से सेवाएं देने और सौंदर्य एवं वेलनेस क्षेत्र में उद्यमिता के नए अवसर तलाशने में सक्षम बन सकें।

यह पहल फिक्की फ्लो जेकेएल की जमीनी स्तर पर महिलाओं को कौशल विकास और टिकाऊ आजीविका के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

फिक्की फ्लो जेकेएल ने अश्वी महाजन की सराहना करते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए उनका नि:स्वार्थ योगदान और विशेषज्ञता प्रेरणादायक है।

एल-जी वीके सक्सेना ने लद्दाख की पुगा घाटी में भारत के पहले दो भू-तापीय कुओं का किया लोकार्पण

कार्बन-न्यूट्रल लद्दाख के प्रधानमंत्री के विजन को मिली नई गति, भारत के पहले भू-तापीय विद्युत परियोजना की दिशा में ऐतिहासिक कदम

लेह, 17 जुलाई। भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए उपराज्यपाल श्री वीके सक्सेना ने आज लद्दाख की पुगा घाटी में ओएनजीसी एनर्जी सेंटर द्वारा विकसित भारत के पहले और सबसे गहरे दो भू-तापीय (जियोथर्मल) कुओं का लोकार्पण किया। यह उपलब्धि लद्दाख में भारत के पहले भू-तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित पुगा घाटी में 1,000-1,000 मीटर गहरे इन दोनों कुओं का निर्माण लद्दाख को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप अक्षय ऊर्जा आधारित स्वच्छ ऊर्जा केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। यह परियोजना प्रधानमंत्री के कार्बन-न्यूट्रल लद्दाख के विजन तथा भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए वैकल्पिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के आह्वान को भी साकार करती है।

ये दोनों भू-तापीय कुएं पुगा में स्थापित किए जाने वाले 1 मेगावाट क्षमता के पायलट भू-तापीय विद्युत परियोजना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह भारत की पहली प्रदर्शन-स्तरीय भू-तापीय विद्युत परियोजना होगी।

उल्लेखनीय है कि लद्दाख प्रशासन, एलएएचडीसी लेह और ओएनजीसी एनर्जी सेंटर के बीच पूर्व में हुए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) की अवधि समाप्त होने के कारण इस परियोजना में कई महीनों की देरी हुई थी। भू-तापीय ऊर्जा के रणनीतिक महत्व को देखते हुए उपराज्यपाल श्री वीके सक्सेना ने स्वयं हस्तक्षेप कर इस वर्ष जून में एमओयू का पांच वर्षों के लिए नवीनीकरण सुनिश्चित कराया, जिसके बाद परियोजना का कार्य दोबारा शुरू हो सका।इन दोनों कुओं के सफल निर्माण से भू-तापीय जलाशय का वैज्ञानिक मूल्यांकन, विद्युत संयंत्र की योजना तथा भविष्य में भू-तापीय संसाधनों के व्यावसायिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।परियोजना से जुड़े अभियंताओं ने बताया कि 400 मीटर की गहराई पर 135 डिग्री सेल्सियस का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। आगे परीक्षण जारी हैं और उम्मीद है कि इससे भी अधिक तापमान प्राप्त होगा, जिससे 1 मेगावाट पायलट परियोजना के संचालन तथा भविष्य में व्यावसायिक स्तर पर भू-तापीय ऊर्जा उत्पादन का मार्ग खुलेगा।

यह परियोजना दुनिया के सबसे कठिन कार्यस्थलों में से एक पुगा घाटी में पूरी की गई है, जहां अत्यधिक ठंड, दुर्गम भूभाग और सीमित कार्य अवधि जैसी कई चुनौतियां मौजूद हैं।

भू-तापीय गतिविधियों, जटिल भूगर्भीय परिस्थितियों और तकनीकी चुनौतियों के बावजूद पहला कुआं 22 मई 2026 को 1,000 मीटर की निर्धारित गहराई तक सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

इसके बाद दूसरा कुआं 3 जून 2026 को शुरू किया गया और मात्र एक महीने से कुछ अधिक समय में 8 जुलाई 2026 को इसे भी 1,000 मीटर की गहराई तक सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इस अवसर पर उपराज्यपाल श्री वीके सक्सेना ने कहा कि इन भू-तापीय कुओं का लोकार्पण भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि तथा लद्दाख के कार्बन-न्यूट्रल भविष्य की दिशा में निर्णायक कदम है।